MR. CHAIRMAN: I did not ...*(Interruptions)*... I did not. The hon. Member took more than his time. I didn't stop him. I would continue with the discussion. Let me just do what is essential.

ANNOUNCEMENT BY THE CHAIR

Re. Panel of Vice-Chairmen

MR. CHAIRMAN: Hon. Members, I have to inform the Members that the Panel of Vice-Chairmen has been reconstituted with effect from 25th June, 2014 with the following Members:

(1) Dr. Satyanarayan Jatiya

(2) Dr. E.M. Sudarsana Natchiappan

(3) Shri Tiruchi Siva

(4) Shri V.P. Singh Badnore

Now, we continue with the discussion, and I call Shri Mukhtar Abbas Naqvi.

DISCUSSION ON PRICE RISE AND INFLATION FACED BY THE COUNTRY–Contd.

श्री मुख्तार अब्बास नक़वी (उत्तर प्रदेश) : आदरणीय सभापति महोदय, मुझे आज इस बात को कहने में बहुत खुशी हो रही है और साथ ही साथ सरकार को मैं बधाई देना चाहता हूं कि ...(व्यवधान)...

[† جناب مختار عبّاس نقوی (اتّر پردیش) : آدرنئے سبھا پتی مہودے، مجھے آج اس بات کو کہنے میں بڑی خوشی ہو رہی ہے اور ساتھ ہی ساتھ سرکار کو میں بدھائی دینا چاہتا ہوں کہ ...(مداخلت)...]

SHRI SITARAM YECHURY (West Bengal): Sir, ...*(Interruptions)*...

MR. CHAIRMAN: Government is also a party in the House. ...*(Interruptions)*...

SHRI SITARAM YECHURY: Yes, he is a party in the House. ...*(Interruptions)*... You may allow him to speak. ...*(Interruptions)*... But the point is that you announced that you are following an order according to the strength in the House. ...*(Interruptions)*... And just before ...*(Interruptions)*...

MR. CHAIRMAN: There is a certain strength in the House. ...*(Interruptions)*...

† Transliteration in Urdu Script.

SHRI SITARAM YECHURY: No, no. But that strength should have come much earlier then. The point is, after the Leader of the Opposition, he should have spoken. That we can understand. Now, suddenly when my turn is about to come, you call him to speak. I have no objection. But the question is, I think, it is a little out of order. ...*(Interruptions)*...

MR. CHAIRMAN: A few minutes back, you were not in the House. ...*(Interruptions)*... Sitaramji, a few minutes back you were not in the House. ...*(Interruptions)*...

SHRI SITARAM YECHURY: They will have the prerogative to answer it. ...*(Interruptions)*... You have all the prerogative. You listen to the Opposition then answer it.

श्री सभापति : आप सुन लीजिए। ...(व्यवधान)...

श्री मुख्तार अब्बास नक़वी : आदरणीय सभापति महोदय, मैं इस सरकार को बधाई देता हूं कि ...(व्यवधान)...

† جناب مختار عبّاس نقوی : آدرنئے سبھاپتی مہودے، میں اس سرکار کو بدھائی دیتا ہوں کہ ...(مداخلت)...

प्रो. राम गोपाल यादव : महंगाई बढ़ाने के लिए? ...(व्यवधान)...

श्री नरेश अग्रवाल : ठीक कह रहे हो। ...(व्यवधान)...

श्री मुख्तार अब्बास नक़वी : 2004 से 2014 तक ...(व्यवधान)... आप सुनिए, तभी तो समझ में आएगा। ...(व्यवधान)...

† جناب مختار عبّاس نقوی : 2004 سے 2014 تک ...(مداخلت)... آپ سنئیے، تبھی تو سمجھ میں آئے گا ...(مداخلت)...

श्री सभापति : प्लीज, प्लीज। ...(व्यवधान)...

श्री मुख्तार अब्बास नक़वी: 2004 से 2014 के बीच में, जब यू.पी.ए. की सरकार थी मुझे कोई भी दिन याद नहीं, जिस दिन महंगाई को लेकर, जिस दिन भ्रष्टाचार को लेकर, जिस दिन घोटालों को लेकर, जिस दिन देश में चौतरफा अव्यवस्था को लेकर, इस सदन में चर्चा कराने के लिए मांग न उठी हो। संसद से सड़क तक बैचेनी रही है, संसद से लेकर सड़क तक आंदोलन होते रहे हैं, लेकिन कोई ऐसा दिन मुझे याद नहीं है, आप तमाम वरिष्ठ सदस्य बैठे हुए हैं, यदि आपको याद हो ...(व्यवधान)... मुझे कोई ऐसा दिन याद नहीं जिसमें सरकार से इस सदन में मांग न की हो, न केवल बी.जे.पी. बल्कि बीच में जो सदस्य बैठे हुए हैं, वे अभी भी बीच में बैठे हैं, उनको मैं कह रहा हूं कि अगर उनको कोई दिन याद हो कि सरकार ने तत्काल महंगाई पर, भ्रष्टाचार पर, घोटालों पर, चर्चा करने को मान लिया हो। इसलिए मैंने सरकार को बधाई दी कि सरकार संवेदनशील है, ईमानदार है और जन-सरोकार से जुड़े हुए मुद्दों पर चर्चा करना चाहती है और इसलिए बधाई की पात्र है।

बजट सत्र का पहला दिन महंगाई पर चर्चा से शुरू हो रहा है, यह बहुत अच्छी बात है। महंगाई आज लोगों को परेशान कर रही है, महंगाई एक सच्चाई है। महंगाई से आम आदमी त्राहि-त्राहि कर

† Transliteration in Urdu Script.

[श्री मुख्तार अब्बास नक़वी]

रहा है, इससे कोई इन्कार नहीं कर सकता, यह एक सच्चाई है और इस सच्चाई से हमें जीना पड़ेगा। लेकिन यह सच्चाई विरासत में किसने दी है? आज से एक महीने पहले जो लोग सरकार में थे, वे आज महंगाई के प्रति इतने चिंतित हैं, मुझे यह अच्छा लग रहा है। मुझे अच्छा लगता जब वे इधर बैठे हुए थे, तब चिंतित होते। हम जिस समय उधर से कह रहे थे कि भाई, भ्रष्टाचार खत्म कर दो, महंगाई खत्म कर दो, कालाजाबारियों पर, जमाखोरों पर और सत्ता के दलालों पर लगाम लगाओ, तो कहते थे कि नहीं, महंगाई है कहां! कहां भ्रष्टाचार है, कहां घोटाला है! भाई, सब कुछ ठीक चल रहा है, आज आम आदमी खुश है। हमें इस बात की खुशी है और हम आपको भी बधाई देते हैं कि कम से कम सत्ता से हटने के बाद, उधर जाते ही आपको एक महीने में महंगाई दिखाई देने लगी। आज यह सरकार संवेदनशीलता के साथ काम कर रही है। आपने जो बोया है अभी तो वही काटा जा रहा है। अगर आपने महंगाई का पूरा का पूरा पौधा खड़ा करके दिया है, तो काटा तो वही जाएगा। आपने भ्रष्टाचार और घोटालों की एक लम्बी श्रृंखला खड़ी की है, उसका असर तो दिखाई, पड़ेगा। लेकिन निश्चित-तौर पर नरेन्द्र मोदी जी की सरकार, बी.जे.पी. और एन.डी.ए. की सरकार ने जो पौधा लगाया है, जो पौध लगाई है, आपको उसकी लहलहाती फसल जल्द दिखाई पड़ेगी। जब आपको यह पौध दिखेगी तो आपको इसी सदन में, जब आप महंगाई पर चर्चा कर रहे हैं, तो आप इस देश के बेहतर हालात पर भी चर्चा करिएगा। **...(व्यवधान)...** जब बात निकलेगी तो दूर तक जाएगी। "उनकी तरक्की के अंदाज निराले थे, चौतरफा करप्शन था, हर ओर घोटाले थे"। अभी तो भैया, आपकी ही नाकामियों पर बहस होगी। अभी तो हमने शुरू किया है, विपक्ष में बैठने के बाद भी, आप तो अपनी ही नाकामियों पर नगाड़ा पीटने लगे, इसलिए चर्चा उसी पर होगी। जब चर्चा होगी, तो आपको सुनना पड़ेगा। चर्चा हमने शुरू नहीं की है, चर्चा आपने शुरू की है। आप देश को उदारवाद के रास्ते पर ले जा रहे हैं। अभी शरद यादव जी कह रहे थे कि देश में गरीबी बढ़ी है, देश का किसान बदहाल है। आप देश को उदारवाद के रास्ते पर ले जा रहे थे, लेकिन देश को कहां ले गए, उधारवाद के रास्ते पर। मैं आपको पूरा आंकड़ा नहीं देना चाहता। पूर्व प्रधान मंत्री जी यहां बैठे हुए हैं। उन्हें मालूम है कि देश कितनी बुरी तरह से ऋण में डूब गया है। आज जो बच्चा पैदा हो रहा है, वह अपने सिर पर बीस हजार से पच्चीस हजार रुपए तक का कर्ज लेकर पैदा हो रहा है। आज देश की यह हालत है। हमें ऐसी हालत विरासत में मिली है। आपने हमें इस तरह की विरासत दी है और आप ऐसे हालात में कह रहे हैं कि महंगाई है। हम कहते हैं कि बिल्कुल महंगाई है। हम आपकी तरह यह बात नहीं कह रहे हैं कि महंगाई बिल्कुल नहीं है, देश बिल्कुल खुशहाल है, देश में चौतरफा रोज़गार सिर चढ़कर बोल रहा है। हम कहते हैं, महंगाई है। आपने हमें घोटालों का घंटाघर दिया है। आपकी सरकार घोटालों की गुरू घंटाल सरकार कहलाई जाने लगी **...(व्यवधान)...** टू जी, फोर जी, कॉमनवेल्थ जी, जीजा जी और न जाने क्या-क्या जी घोटाले हुए और घोटालों पर घोटाले, घोटालों पर घोटाले, उसका असर देश पर पड़ा और देश की अर्थव्यवस्था पर भी पड़ा तथा देश चौतरफा बदहाली और बेहाली के कगार पर खड़ा हुआ। आज सरकार निश्चित तौर से संवेदनशीलता के साथ काम रही है, जिसकी वजह से देश में बदलाव का माहौल दिखने लगा है। यह बात सही है कि जमाखोरों के लिए, कालाबाजारियों के लिए और सत्ता के दलालों के लिए बुरे दिन आ गए हैं। उनके लिए बुरे दिन आना ही देश के गरीबों के लिए अच्छे दिन की गारंटी है। जब जमाखोरों, सत्ता के दलालों और कालाबाजारियों के लिए बुरे दिन हैं, तो वे तो चौतरफा चिल्लाएंगे कि साहब, बिल्कुल कुछ नहीं हो रहा है। हमने दस सालों में जितना कमाया था, वह एक महीने में गंवा रहे हैं। जो रुपया पहले कंगाल हो गया था और डॉलर मालामाल हो गया था, अब वह रुपया मालामाल होने लगा

और डॉलर कंगाल होने लगा है। देश में इस तरह का एक बदलाव आया है। सबसे पहले उस समय सरकार का इकबाल है। जब कोई सरकार बनती है, तो सबसे पहले उस सरकार का इकबाल देखा जाता है कि उसमें वह इकबाल है या नहीं है? उस समय सरकार के मंत्री, सुपर प्राइम मिनिस्टर, फलां प्राइम मिनिस्टर, ये बेचारे प्रधान मंत्री जी, जो उस समय थे। ...**(व्यवधान)**...

श्री सभापति : आप समाप्त कीजिए।

श्री मुख्तार अब्बास नक़वी : ये चाहते बहुत कुछ थे, लेकिन इतने सुपर प्राइम मिनिस्टर थे कि इनके चाहने के बाद भी कुछ नहीं कर रहे थे। आज सरकार का इकबाल भी हैं, सरकार कुछ करना भी चाहती है और सरकार इस देश को ईमानदारी व संवेदनशीलता के साथ बेहतर रास्ते पर, कामयाबी के रास्ते पर ले जाना चाहती है। ...**(व्यवधान)**...

MR. CHAIRMAN: Thank you ...*(Interruptions)*... One minute ...*(Interruptions)*...

श्री मुख्तार अब्बास नक़वी : उस कामयाबी के रास्ते पर देश की गाड़ी सरपट दौड़ेगी, ...**(व्यवधान)**...

SHRI ANAND SHARMA (Rajasthan): Sir, I have to say something.

श्री मुख्तार अब्बास नक़वी : आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। ...**(व्यवधान)**...

MR. CHAIRMAN: Thank you. आपका समय समाप्त हो गया, आप बैठ जाइए। ...**(व्यवधान)**...

श्री मुख्तार अब्बास नक़वी : देश की गाड़ी सरपट दौड़ रही है। ...**(व्यवधान)**...

MR. CHAIRMAN: Please ...*(Interruptions)*... नकवी साहब, आपका समय समाप्त हो गया। ...**(व्यवधान)**...

श्री मुख्तार अब्बास नक़वी : आपने एल.पी.जी. के दाम, डीजल के दाम ...**(व्यवधान)**...

SHRI ANAND SHARMA: Sir, I have to say something.

SHRI MUKHTAR ABBAS NAQVI: I am not yielding. ...*(Interruptions)*... Sir, I am not yielding. ...*(Interruptions)*...

SHRI ANAND SHARMA: If you will talk to me disrespectfully, ...*(Interruptions)*... You are nobody to tell me. I am requesting the hon. Chairman. ...*(Interruptions)*...

MR. CHAIRMAN: Please...*(Interruptions)*...

श्री मुख्तार अब्बास नक़वी : आपने पेट्रोल के दाम ...**(व्यवधान)**... जब आप चर्चा कर रह थे। ...**(व्यवधान)**... हमारे नेता विरोधी दल जब चर्चा कर रहे थे, तो उनको यह बताना चाहिए था। ...**(व्यवधान)**...

श्री सभापति : आप बैठ जाइए। ...(व्यवधान)... अब आप खत्म कीजिए।

श्री मुख्तार अब्बास नक़वी : आपने इन दस सालों में डीजल के कितने दाम बढ़ाए? आपको बताना चाहिए था कि इन दस सालों में आपने गरीबों के चौकों-चूल्हों तक एल. पी. जी. क्यों नहीं पहुंचने दी? ...(व्यवधान)...

MR. CHAIRMAN: Please conclude.

श्री मुख्तार अब्बास नक़वी : आपको यह भी बताना चाहिए था कि इस दस सालों में जो गरीब केरोसीन ऑयल इस्तेमाल करता है, आपने उनके दाम दिन दूने-रात चौगुने क्यों बढ़ाए? आप हमारी सरकार से कहते हैं कि डीजल का दाम बढ़ गया। डीजल का दाम कहां बढ़ गया? यह पचास पैसे बढ़ गया। आप पचास रुपये बढ़ायें और यदि हम पचास पैसे बढ़ाएं तो आपको लगता है कि महंगाई बहुत बढ़ गई। "हम आह भी करते हैं तो बदनाम, तुम कत्ल भी करते हो तो चर्चा नहीं होती।"

MR. CHAIRMAN: Please conclude. Thank you. आप खत्म कीजिए, आपका समय खत्म हो गया है ...(व्यवधान)...

श्री मुख्तार अब्बास नक़वी : मिट्टी के तेल के दाम नहीं बढ़े ...(व्यवधान)... आपको इस बात को समझना होगा कि आपने हमें जो महंगाई की, भ्रष्टाचार की और नाकामियों की विरासत दी है, उसे ठीक करने के संकल्प के साथ यह सरकार काम कर रही है ...(व्यवधान)... और हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि देश के गरीबों, देश की जनता और देश के आप लोगों के लिए अच्छे दिन आएंगे ...(व्यवधान)... आपके अच्छे दिन आएं, इसकी गारंटी नहीं है ..(व्यवधान)...

†[جناب مختار عباس نقوی : 2004 سے 2014 کے بیچ میں، جب یو.پی.اے. کی سرکار تھی مجھے کوئی بھی دن یاد نہیں، جس دن مہنگائی کو لے کر، جس دن بھرشٹاچار کو لے کر، جس دن دیش میں چوطرفہ آویوستھا کو لے کر، اس سدن میں چرچا کرانے کے لئے مانگ نہ اٹھی ہو۔ سنسد سے سڑک تک بے چینی رہی ہے، سنسد سے لے سڑک تک آندولن ہوتے رہے ہیں، لیکن کوئی ایسا دن مجھے یاد نہیں ہے، آپ تمام ورشٹھ سدسنے بیٹھے ہیں، اگر آپ کو یاد ہو ...(مداخلت)... مجھے کوئی ایسا دن یاد نہیں جس میں سرکار سے اس سدن نے مانگ نہ کی ہو، نہ کیول بی.جے.پی. بلکہ بیچ میں جو سدسنے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ ابھی بھی بیچ میں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو میں کہہ رہا ہوں کہ اگر ان کو کوئی دن یاد ہو کہ سرکار نے

† Transliteration in Urdu Script.

تکنال مہنگائی پر، بھرشٹاچار پر، گھوٹالور پر، چرچہ کرنے کو مان لیا ہو۔ اس لئے میں نے سرکار کو بدھائی دی کہ سرکار سنویدن-شیل ہے، ایماندار ہے اور جن-سروکار سے جڑے ہوئے مدّعوں پر چرچہ کرنا چاہتی ہے اور اس لئے بدھائی کی پاتر ہے۔

بجٹ سیشن کا پہلا دن مہنگائی پر چرچا سے شروع ہو رہا ہے، یہ بہت اچھی بات ہے۔ مہنگائی آج لوگوں کو پریشان کر رہی ہے، مہنگائی ایک سچّائی ہے۔ مہنگائی سے عام آدمی تراہی-تراہی کر رہا ہے، اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا، یہ ایک سچّائی ہے اور اس سچائی سے ہمیں جینا پڑے گا۔ لیکن یہ سچّائی وراثت میں کس نے دی ہے؟ آج سے ایک مہینے پہلے جو لوگ سرکار میں تھے، وہ آج مہنگائی کے پرتی اتنے چنتت ہیں، مجھے یہ اچھا لگ رہا ہے۔ مجھے اچھا لگتا جب وہ ادھر بیٹھے ہوئے تھے، تک چنتت ہوتے۔ ہم جس وقت ادھر سے کہہ رہے تھے کہ بھائی، بھرشٹاچار ختم کر دو، مہنگائی ختم کردو، کالابازاریوں پر، جمع-خوروں پر اور ستّہ کے دلالوں پر لگام لگاؤ، تو کہتے تھے کہ نہیں، مہنگائی ہے کہاں۔ کہاں بھرشٹاچار ہے، کہاں گھوٹالہ ہے! بھائی، سب کچھ ٹھیک چل رہا ہے، آج عام آدمی خوش ہے۔ ہمیں اس بات کی خوشی ہے اور ہم آپ کو بھی بدھائی دیتے ہیں کہ کم سے کم ستّہ سے ہٹنے کے بعد، ادھر جاتے ہی آپ کو ایک مہینے میں مہنگائی دکھائی دینے لگی۔ آج یہ سرکار سنویدن-شیلتا کے ساتھ کام کر رہی ہے۔ آپ نے جو بویا ہے ابھی تو وہی کاٹا جا رہا ہے۔ اگر آپ نے مہنگائی پر پورا کا پورا پودھا کھڑا کرکے دیا ہے، تو کاٹا تو وہی جائے گا۔

آپ نے بھرشٹاچار اور گھوٹالوں کی ایک لمبی لائن کھڑی کی ہے، اس کا اثر تو دکھائی پڑے گا۔ لیکن یقینی طور سے نریندر مودی جی کی سرکار، بی-جے-پی۔ اور این-ڈی-اے۔ کی سرکار نے جو پودھا لگایا ہے، جو پودھہ لگائی ہے، آپ کو اس

[श्री मुख्तार अब्बास नकवी]

کی لہلہاتی فصل دکھائی پڑے گی۔ جب آپ کو یہ پودھا دکھے گا تو آپ کو اسی سدن میں، جب آپ مہنگائی پر چرچا کر رہے ہیں، تو آپ اس دیش کے بہتر حالات پر بھی چرچا کرنے گا ...(مداخلت).... جب بات نکلے گی تو دور تک جائے گی "ان کی ترقی کے انداز نرالے تھے، چوطرفہ کرپشن تھا، ہر اور گھوٹالے تھے" ابھی تو بھئیا، آپ کی ہی ناکامیوں پر بحث ہوگی۔ ابھی تو ہم نے شروع کیا ہے، وپکش میں بیٹھنے کے بعد بھی، آپ تو اپنی ہی ناکامیوں پر نگاڑا پیٹنے لگے، اس لئے چرچا اسی پر ہوگی۔ جب چرچا ہوگی، تو آپ کو سننا پڑے گا۔ چرچا ہم نے شروع نہیں کی ہے، چرچا آپ نے شروع کی ہے۔ آپ دیش کے ادارویذ کے راستے پر لے جا رہے ہیں۔ ابھی شردیادو جی کہہ رہے تھے کہ دیش میں غریبی بڑھی ہے، دیش کا کسان بدحال ہے۔ آپ دیش کو ادارواد کے راستے پر لے جا رہے تھے، لیکن دیش کو کہاں لے گئے، 'ادھارواد' کے راستے پر۔ میں آپ کو پورا آنکڑا نہیں دینا چاہتا۔ سابق پردھان منتری جی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ انہیں معلوم ہے کہ دیش کتنی بری طرح سے قرض میں ڈوب گیا ہے۔ آج جو بچہ پیدا ہو رہا ہے، وہ اپنے سر پر بیس ہزار سے پچیس ہزار روپے تک کا قرض لے کر پیدا ہو رہا ہے۔ آج دیش کی یہ حالت ہے۔ ہمیں ایسی حالت وراثت میں ملی ہے۔ آپ نے ہمیں اس طرح کی وراثت دی ہے اور آپ ایسے حالات میں کہہ رہے ہیں کہ مہنگائی ہے۔ ہم کہتے ہیں بالکل مہنگائی ہے۔ ہم آپ کی طرح یہ بات نہیں کہہ رہے ہیں کہ مہنگائی بالکل نہیں ہے، دیش بالکل خوشحال ہے، دیش میں چوطرفہ روزگار سر چڑھ کر بول رہا ہے۔ ہم کہتے ہیں، مہنگائی ہے۔ آپ نے ہمیں گھوٹالوں کا گھنٹہ گھر دیا ہے۔ آپ کی سرکار گھوٹالوں کی گرو گھنٹال سرکار کہلائی جانے لگی ...(مداخلت)...ٹو جی۔ فور جی، کامن ویلتھ جی، جیجا جی، اور نہ جانے کیا کیا 'جی' گھوٹالے ہوئے اور گھوٹالوں پر گھوٹالے، گھوٹالوں پر

گھوٹالے، اس کا اثر دیش پر پڑا اور دیش کی ارتھ-وبویستھا پر بھی پڑا اور دیش چوطرفہ بدحالی اور بے حالی کے کگار پر کھڑا ہوا ہے۔ آج سرکار نشچت طور سے سنویدن-شیلتا کے ساتھ کام کر رہی ہے، جس کی وجہ سے دیش میں بدلاؤ کا ماحول دکھنے لگا ہے۔ یہ بات صحیح ہے کہ جمع-خوروں کے لئے، کالابازاریوں کے لئے اور سٹہ کے دلالوں کے لئے برے دن آ گئے ہیں۔ ان کے لئے برے دن آنا ہی دیش کے غریبوں کے لئے اچھے دن کی گارنٹی ہے۔ جب جمع-خوروں، سٹہ کے دلالوں اور کالابازاریوں کے لئے برے دن آئے، تو وہ تو چوطرفہ چلائیں گے کہ صاحب، بالکل کچھ نہیں ہو رہا ہے۔ ہم نے دس سالوں میں جتنا کمایا تھا، وہ ایک مہینے میں گنوا رہے ہیں۔ جو روپیہ پہلے کنگال ہو گیا تھا اور ڈالر مالامال ہو گیا تھا، اب وہ روپیہ مالامال ہونے لگا اور ڈالر کنگال ہونے لگا ہے۔ دیش میں اس طرح کا ایک بدلاؤ آیا ہے۔ سب سے بڑا بدلاؤ سرکار کا اقبال ہے۔ جب کوئی سرکار بنتی ہے، تو سب سے پہلے اس سرکار کا اقبال دیکھا جاتا ہے کہ اس میں وہ اقبال ہے یا نہیں ہے؟ اس سمے سرکار کے منتری، سپر پرائم منسٹر، فلاں پرائم منسٹر، یہ بے چارے پردھان منتری جی، جو اس سمے تھے ...(مداخلت)...

شری سبھا پتی : آپ سماپت کیجئے۔

جناب مختار عباس نقوی : یہ چاہتے بہت کچھ تھے، لیکن اتنے سپر پرائم منسٹر تھے کہ ان کے چاہنے کے بعد بھی کچھ نہیں کر رہے تھے۔ آج سرکار کا اقبال بھی ہے، سرکار کچھ کرنا بھی چاہتی ہے اور سرکار اس دیش کو ایمانداری اور سنویدن-شیلتا کے ساتھ بہتر راستے پر، کامیابی کے راستے پر لے جانا چاہتی ہے ...(مداخلت)...

MR. CHAIRMAN: Thank you... *(Interruptions)*... One minute ... *(Interruptions)*...

[Mr. Chairman]

†[**جناب مختار عبّاس نقوی :** اس کامیابی کے راستے پر دیش کی گاڑی سرپٹ دوڑے گی ...(مداخلت)...]

SHRI ANAND SHARMA: Sir, I have to say something.

†[**جناب مختار عبّاس نقوی :** آپ کو چنتا کرنے کی ضرورت نہیں ہے ...(مداخلت)...

شری سبھا پتی : تھینک یو، آپ کا سمے سماپت ہو گیا، آپ بیٹھ جائیے ...(مداخلت)...

جناب مختار عبّاس نقوی : دیش کی گاڑی سرپٹ درڑ رہی ہے...(مداخلت)...

شری سبھا پتی : پلیز...(مداخلت)... نقوی صاحب، آپ کا سمے ختم ہو گیا ...(مداخلت)...

جناب مختار عبّاس نقوی : آپ نے ایل.پی.جی. کے دام، ڈیزل کے دام ...(مداخلت)...]

SHRI ANAND SHARMA: Sir, I have to say something.

SHRI MUKHTAR ABBAS NAQVI: I am not yielding. ...*(Interruptions)*... Sir, I am not yielding. ...*(Interruptions)*...

SHRI ANAND SHARMA: If you will talk to me disrespectfully, ...*(Interruptions)*... You are nobody to tell me. I am requesting the hon. Chairman. ...*(Interruptions)*...

MR. CHAIRMAN: Please... *(Interruptions)*...

†[**جناب مختار عبّاس نقوی :** آپ پیٹرول کے دام ...(مداخلت)... جب آپ چرچا کر رہے تھے ...(مداخلت)... ہمارے نیتا ورودھی دل جب چرچا کر رہے تھے، تو ان کو یہ بتانا چاہئے تھا...(مداخلت)...

شری سبھا پتی : آپ بیٹھ جائیے ...(مداخلت)... اب آپ ختم کیجئے۔]

جناب مختار عبّاس نقوی : آپ نے ان دس سالوں میں ڈیزل کے کتنے دام بڑھائے؟ آپ کو بتانا چاہئے تھا کہ ان دس سالوں میں آپ نے غریبوں کے چوکوں-چولہوں تک ایل.پی.جی. کیوں نہیں پہنچنے دی؟ ...(مداخلت)...†

† Transliteration in Urdu Script.

MR. CHAIRMAN: Please conclude.

جناب مختار عباس نقوی : آپ کو یہ بھی بتانا چاہئے تھا کہ ان دس سالوں میں جو غریب کیروسن آئل استعمال کرتا ہے ، آپ نے اس کے دام دن دونے-رات چوگنے کیوں بڑھائے؟ آپ ہماری سرکار سے کہتے ہیں کہ ڈیزل کا دام بڑھ گیا. ڈیزل کا دام کہاں بڑھ گیا؟ یہ پچاس پیسے بڑھ گیا. آپ پچاس روپے بڑھائیں اور اگر یہ پچاس پیسے بڑھائیں تو آپ کو لگتا ہے کہ مہنگائی بہت بڑھ گئی. "ہم آہ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام، تم قتل بھی کرتے ہو تو چرچا نہیں ہوتی".

شری سبھا پتی : پلیز کنکلوڈ، تھینک یو، آپ ختم کیجئے، آپ کا سمے ختم ہو گیا ہے ...(مداخلت)...

جناب مختار عباس نقوی : مٹّی کے تیل کے دام نہیں بڑھے ...(مداخلت)... آپ کو اس بات کو سمجھنا ہوگا کہ آپ نے ہمیں جو مہنگائی کی، بھرشٹاچار کی اور ناکامیوں کی وراثت دی ہے، اسے ٹھیک کرنے کے سنکلپ کے ساتھ یہ سرکار کام کر رہی ہے ...(مداخلت)... اور ہم آپ کو وشواس دلاتے ہیں کہ دیش کے غریبوں، دیش کی جنتا اور دیش کے عام لوگوں کے لئے اچھے دن آئیں گے ...(مداخلت)... آپ کے اچھے دن آئی، اس کی گارنٹی نہیں ہے ...(مداخلت)...

(ختم شد)†

MR. CHAIRMAN: Thank you. Now, Shri Sitaram Yechury.

श्री सीताराम येचुरी: सभापति जी, बहुत-बहुत धन्यवाद। सरकार की तरफ से सुनने के बाद मैं थोड़ा कंफ्यूज्ड हूं कि बहस किसके ऊपर चल रही है। अगर यहां पर महंगाई का सवाल है, अगर यह कहना है कि हमें यहां से विरासत मिली है और हम उस विरासत को आगे ले जा रहे हैं, तो यह लग रहा है कि यह एक रिले रेस चल रही है, जिसमें उनको यहां से बेटन दी गई है, वे उसको पकड़कर दौड़ रहे हैं और महंगाई को बढ़ाए जा रहे हैं। आप दौड़ेंगे और कहेंगे कि लोगों ने हमें अधिकार दे दिया है, पेन्डेट दे दिया है। यह बिल्कुल सही है कि लोगों ने पेन्डेट दिया है। यह हमने स्वीकार किया है और हम उसकी इज्जत करते हैं, लेकिन लोगों ने इसलिए पेन्डेट नहीं दिया है कि आप उनकी जिंदगी पर हमला करें, लोगों ने इसलिए पेन्डेट नहीं दिया है कि आप महंगाई बेहद बढ़ाते जाएं। लोगों ने पेन्डेट इसलिए दिया है कि आपने उनके सामने जो वादे किए हैं, आप उन वादों को पूरा करें। अगर आप में

† Transliteration in Urdu Script.

[श्री सीताराम येचुरी]

किए गए वादों को पूरा करने की सक्षमता नहीं है, तो उसको स्वीकार कराने की जिम्मेदारी विपक्ष में हमारी है। आप जब इधर बैठे थे, तो इस सवाल पर आप हमारे साथ थे, आज उधर बैठे हैं तो आपके द्वारा उसका विरोध करना, हमें समझ में नहीं आ रहा है।

महंगाई के सवाल पर अभी एक अजीबोगरीब बात कही गई कि इन्होंने पचास रुपये बढ़ाए और हमने पचास पैसे बढ़ाए। इसमें क्या फर्क है? यानी 49 रुपये और 50 पैसे बढ़ाने का अधिकार आपने ऑलरेडी अपने आप ले लिया है। आप इसको और बढ़ाएंगे। आप इसको उस हद तक बढ़ाएंगे, क्योंकि उन्होंने बढ़ाए थे। अगर महंगाई पर बात हो रही है तो यहां पर सवाल यह नहीं है कि जब ये सत्ता में थे या जब ये सत्ता में हैं, यहां पर कांग्रेस-बी.जे.पी. के बीच में भी सवाल नहीं है। जब इन्होंने कुछ कदम नहीं उठाए, जिसकी वजह से दाम बढ़ रहे थे, तब हमने उनका भी विरोध किया था और करते भी रहे हैं, और अब इन वादों पर यह सरकार हुकूमत करने के लिए आई है कि वे जो गलत काम हुए हैं, उनको सुधारेंगे। लेकिन हम पहले ही दिन से क्या देख रहे हैं कि आप उन्हीं कामों को आगे ले जा रहे हैं। डीजल का दाम पचास पैसे बढ़ा या पचास रुपये बढ़ा, लेकिन उसकी वजह से दाम तो बढ़े ही हैं। आपने कुकिंग गैस एल.पी.जी. का दाम तो बढ़ाया है और यह सच है कि वे दाम भी बढ़े हैं। कारण जो कुछ भी हैं, मैं उन कारणों पर भी आऊंगा, लेकिन सवाल यह है कि कल रेल बजट आ रहा है, उससे दो हफ्ते पहले आप रेल फेयर के दाम बढ़ा देते हैं? मुझे याद है कि जब मैं इसी जगह से बोल रहा था, तो जो हाउस के लीडर हैं, वे वहां पर एल.ओ.पी. थे, उन्होंने इस पर बोला था। हमारे आज के प्रधान मंत्री साहब, उनकी जो आदत है, उनका जो कम्युनिकेशन का, ट्वीट का वन वे ट्रैफिक है, उन्होंने उस ट्वीट पर कहा था कि सदन शुरू होने से पहले दाम बढ़ाना पार्लियामेंट्री परम्परा में गलत है। यह बिल्कुल गलत है, इस बारे में हमारी उनके साथ सौ फीसदी सहमति है, लेकिन आपने आज वही काम क्यों किया? आप इसका जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं? सवाल यह है कि आज रेल के दाम बढ़ने से, डीज़ल के दाम बढ़ने से पेट्रोलियम पदार्थों के दाम बढ़ने से यह महंगाई बेहद बढ़ रही है। लीडर ऑफ दि अपोजिशन ने इसके पूरे आंकड़े दिए हैं, मैं आपका समय बचाने के लिए उनको दोहराना नहीं चाहता हूं। इसके अलावा और भी कई सारी बातें हैं, जिनको अभी शरद जी ने बताया है। मैं कहना चाहता हूं कि सिर्फ फूड आइटम्स ही नहीं, लेकिन बाकी सारी चीजों के जो दाम बढ़ रहे हैं, उन पर कैसे अंकुश लगेगा? मेरे हिसाब से यह पूछना सदन की जिम्मेदारी है कि आप इस पर कैसे अंकुश लगाएंगे और जनता के लिए हमें जिम्मेदारी निभाने की जरूरत है। मेरे पास कुछ सुझाव हैं और मैं चाहता हूं कि सरकार इन सुझावों को सुने। मैं जानना चाहता हूं कि जब सरकार विपक्ष में थी, तो उस समय दोनों के बीच में इन बातों पर सहमति थी, लेकिन आज इन बातों पर वही सहमति क्यों नहीं बन रही है? हम आपसे यही बात कहना चाहते हैं कि कौन सरकार में है, सवाल यह नहीं है, सवाल है देश की जनता और आज जो ये दाम बढ़ रहे हैं। आपने कह दिया कि जो फूड आइटम्स के दाम बढ़ रहे हैं, उसके लिए डी-होर्डिंग करना जरूरी है। बिल्कुल जरूरी है, लेकिन डी-होर्डिंग से ही पूरा काम नहीं होता। यहां पर मैं आपकी इजाजत चाहूंगा कि आप याद करिए कि आपने एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट के अन्दर एक अमेंडमेंट लाया गया था, जब एन.डी.ए. की सरकार थी और वाजपेयी साहब प्रधान मंत्री थे। उस एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट के अन्दर आपने एसेंशियल कमोडिटीज़ में फॉर्वर्ड ट्रेडिंग, फ्यूचर्स ट्रेडिंग और स्पेकुलेशन के लिए अनुमति दी थी। जब यह अमेंडमेंट आया, तो हमने यहां से उठ कर कहा था कि इसकी वजह से महंगाई बहुत बढ़ रही। एसेंशियल कमोडिटीज़ पर जितना स्पेकुलेशन होगा, उतनी महंगाई बढ़ेगी। उस समय जो एल.ओ.पी. थे, वे आज लीडर ऑफ द हाउस हैं। मुझे याद है कि उस समय उन्होंने कहा था कि सही बात है कि हमारे समय में यह अमेंडमेंट किया गया, लेकिन

आज बढ़ते हुए दामों को ध्यान में रखते हुए इसके बारे में पुनर्विचार करने का समय आ गया है। वित्त मंत्री साहब, आपको याद होगा शरद यादव जी, जिन्होंने आज शपथ ली है, आज हमारे साथ जुड़े हैं, ये उस समय खाद्य मंत्री थे। इन्होंने यह कहा था, मैं अपनी मेमोरी से कोट कर रहा हूं, कि जी हां, हमने फूड ग्रेंस को स्पेकुलेशन में, फ्यूचर्स मार्केट में अलाऊ किया, लेकिन इन्होंने सदन में कहा कि इसके ऊपर पुनर्विचार करने के लिए आज समय आ गया है। मैं ठीक कह रहा हूं न! इन्होंने खुद कहा, जब ये एन.डी.ए. सरकार में मंत्री थे। तब के एल.ओ.पी. आज वित्त मंत्री हैं। जो उस समय खाद्य मंत्री थे, उन्होंने स्वीकार किया, तो आज यह सरकार इसे क्यों स्वीकार नहीं कर रही है? जो 14 एसेंशियल कमोडिटीज़ हैं, आप उनकी फ्यूचर्स और फॉर्वर्ड ट्रेडिंग के ऊपर पाबंदी लगाइए। सर, यह बात केवल अपने देश के अन्दर ही नहीं, बल्कि दुनिया के अन्दर हो रही है। यूनाइटेड नेशंस के रैपर्टियर की एक रिपोर्ट है। यह रिपोर्ट यह कहती है कि दुनिया के अन्दर फूड प्राइसेज की इंफ्लेशन के अन्दर 70 फीसदी कंट्रीब्यूशन स्पेकुलेशन का है और शिकागों की कमोडिटीज़ मार्केट में यह सबसे बड़ा एक्चुअल कारण है, जिसकी वजह से प्राइसेज राइज कर रही हैं। ऑयल प्राइसेज और फूड प्राइसेज, दोनों में, the main culprit is your commodity exchange in Chicago, and 70 per cent -- this is the United Nations rapporteur's report -- of the global prices of fuel and food are rising because of speculation. With that in mind, it is not only de-hoarding, आप स्पेकुलेशन को बंद करिए। अगर आप यह कदम उठाएंगे, जिसे आपने स्वीकार किया था, जब आप इधर बैठे थे, जब ये मंत्री थे, तब इन्होंने मंत्री होते हुए इसे स्वीकार किया था, तो अच्छा होगा। अब यह काम क्यों नहीं हो रहा है, यह सवाल है, जिसका हमें जवाब चाहिए। अगर आप जनता को अच्छे दिन दिखाना चाहते हैं, तो आपको यह काम तुरंत करना होना, वरना आप इस महंगाई पर अंकुश नहीं लगा पाएंगे।

सर, दूसरी बात है कि आपके पास आज बफर स्टॉक में फूडग्रेंस का स्टॉक है। आपके बफर स्टॉक का जो नॉर्म है, उससे दुगुना फूडग्रेंस आपके सरकारी गोडाउंस के अन्दर रॉट हो रहा है। यह जो बफर स्टॉक से ऊपर एक्स्ट्रा फूडग्रेंस है, उसको आप ओपन मार्केट में बी.पी.एल. की प्राइसेज पर क्यों रिलीज नहीं करते हैं? अगर आप उसे रिलीज करेंगे, तो अपने आप इस महंगाई पर अंकुश लगेगा। इन दोनों कामों के लिए हमारे सुझाव की जरूरत नहीं है। ये दोनों ऐसी बातें हैं, जिनके बारे में एक जमाने में सहमति थी, लेकिन आज जब आप सरकार में आ गए, तो आप कहते हैं कि विरासत यहां से आई। जब ये लोग थे, तो इनको भी हम यही समझाते थे, जब ये वहां बैठे थे, कि दोनों काम करिए। यह नहीं हुआ, तो डी होर्डिंग के साथ-साथ आपसे हमारा आग्रह है कि आप एसेंशियल कमोडिटीज को स्पेकुलेटिव ट्रेडिंग में बैन करिए। ठीक है, अगर आप समझते हैं कि यह जरूरी है, तो at least for the time being इनको टेम्पोररली बैन करिए और देखिए कि उसका असर क्या है, तब आपको पता चलेगा कि इसे करना है या नहीं। दूसरी बात यह है कि फूड स्टॉक को रिलीज़ करिए। तीसरा, सर, प्लीज मैं एक मिनट और लूंगा और मैं चाहूंगा कि ये इन बातों पर जवाब दें।

सर, आज के वित्त मंत्री जब लीडर ऑफ द अपोजिशन थे, उस समय उनकी इस बात पर मुझसे सहमति थी। आज पेट्रोलियम प्राइसेज़ के बढ़ने पर यह बात हो रही है कि ईरान में जो हो रहा है, सीरिया में जो हो रहा है या गल्फ में जो हो रहा है, उसकी वजह से पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के दाम बढ़ रहे हैं और चूंकि यह एक अतर्राष्ट्रीय समस्या है, इसलिए हमारे पास इसके अतिरिक्त और कोई चारा नहीं है। सर, मैं चाहता हूं कि इस बात पर आप मुझे एक मिनट बोलने का समय और दें। आज हमारी सभी ऑयल कम्पनीज़ अपनी-अपनी बैलेंस शीट्स में मुनाफे दिखा रही हैं, तो घाटा कहां से हो रहा है? सब ऑयल कम्पनीज मुनाफे में हैं, तो कहां से सब्सिडी का यह ग्रेट लॉस हो रहा है?

(श्री उपसभापति पीठासीन हुए)

आज यह जो अंडर रिकवरीज़ की बात कह रहे हैं, यह समझ लीजिए कि यह अंडर रिकवरी सबसे बड़ा फ्रॉड है, जो देश के अंदर चलाया जा रहा है। अंडर रिकवरीज क्या है? पेट्रोल का जो इंटरनेशनल प्राइस है और देश के अन्दर इसका जो दाम है, इन दोनों के बीच का जो फर्क है, उसी को आप अंडर रिकवरीज कहते हैं। हमारा 98% जो इम्पोर्ट होता है, वहा क्रूड ऑयल का होता है, फिर वह क्रूड ऑयल अपने देश की रिफाइनरी में रिफाइन होता है और वहां से ही पेट्रोल, डीजल और कैरोसिन का दाम इस देश में क्या होना चाहिए? अपनी जो इम्पोर्ट कॉस्ट है और देश के अन्दर जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, प्लस प्रॉफिट मार्जिन, ट्रांस्पोर्टेशन वगैरह को ले लीजिए, वही इनका दाम होना चाहिए। लेकिन आप दाम को कैसे फिक्स करते हैं? आप अंतर्राष्ट्रीय दाम पर इसके दाम फिक्स करते हैं। आप बताइए, क्या इसका कोई मतलब है? इस तरह आप पूरे देश को गुमराह करते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय दाम के मुकाबले में इतने लाख करोड़ का घाटा हो रहा है और इस घाटे को पूरा करने के लिए दाम बढ़ाने के अलावा और कोई चारा नहीं है। अरे भाई, पूरे देश में यह एक बहुत बड़ा फ्रॉड हो रहा है।

यह काम किसने शुरू किया? सवाल यह नहीं है कि यह काम उन्होंने शुरू किया या फिर आपने उसी विरासत को ग्रहण कर लिया, लेकिन अब मौका है कि आप इस परम्परा को बदलिए और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के आधार पर दाम फिक्स करिए। ऐसा करने से आपको तेल के दाम बढ़ाने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। इससे आप देश को बहुत बड़ी राहत दे सकेंगे।

सर, यह मेरा लास्ट प्वाइंट है। सर, अभी गरीबी के बारे में रंगराजन कमेटी की रिपोर्ट आई है। देश में यह क्या मज़ाक हो रहा है? आप कहते हैं कि अगर आपके पास शहर में 47 रुपये हैं, तो आप गरीब नहीं हैं। पहले जब तेंदुलकर कमेटी ने 32 रुपये कहा था, तब सब जगह हल्ला मच गया था और बिल्कुल सही हल्ला मचा था तब चुनाव चल रहे थे और हम लोगों की बात हंसी-मज़ाक में उड़ा दी गई थी। प्रधान मंत्री ने स्वयं इसके बारे में ट्वीट किया था। तब तेंदुलकर कमेटी ने 32 रुपये कहा, अगर उसमें आप आज की महंगाई को जोड़ दीजिए तो वह फिगर कहां पहुंचेगी? वह फिगर 60 रुपये से ज्यादा पहुंच जाएगी। आज जो नयी कमेटी आई है, वह कहती है कि अगर आपके पास 47 रुपये हैं, तो आप गरीब नहीं हैं। सर, हम किसको बेवकूफ बना रहे हैं? यह संसद है, यह सदन है। जनता चाहती है कि **...(व्यवधान)...**

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Yechury sahib, please conclude.

SHRI SITARAM YECHURY : I am concluding, sir. It is my last point.

पूरी बात कहने के पीछे मेरा मकसद सिर्फ यह है कि प्लीज, अब संसद को गुमराह करने की परम्परा को बन्द करने की जरूरत है।

सर, मैंने तीन-चार गिनवाए हैं, जिनको मैं एक बार फिर से दोहरा रहा हूं। पहली बात, डीहोर्डिंग के साथ-साथ आप फॉरवर्ड और फ्यूचर्स ट्रेडिंग में एसेंशियल कमॉडिटीज़ को बैन करिए।

दूसरी बात, जितना एक्सेस स्टॉक है, आप उसको मार्किट में बी.पी.एल. दाम पर रिलीज करिए, वह अपने आप महंगाई को कम करेगा।

तीसरा, अंडर रिकवरीज का यह जो बहाना है, उस फ्रॉड को बन्द करिए और सीधे-सीधे बैलैंस शीट में जो मुनाफा बनता है, उस हिसाब से आप उसको कैल्कुलेट करिए। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के

ऊपर आप तय करिए कि दाम क्या होना चाहिए। जो सुझाव उस समय एल.ओ.पी. ने दिए थे, जो आज स्वयं वित्त मंत्री हैं और जो सुझाव उस समय के हमारे खाद्य मंत्री, शरद जी ने दिए थे, आप उन पर गौर कीजिए। एसेंशियल कमॉडिटीज ऐक्ट के अन्दर जो अमेंटडमेंट लाया गया था, for the time being, आप उस अमेंडमेट को सस्पेंड करिए और महंगाई पर अंकुश लगाइए।

चौथा, पावर्टी के जो आंकड़े हैं, उन आंकड़ों के आधार पर आप ज्यादा कुछ निर्णय मत लीजिए **...(समय की घंटी)**

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please conclude.

श्री सीताराम येचुरी : सर, रंगराजन कमेटी के आंकड़ों के मुताबिक भी, इस फॉल्टी फिगर के साथ भी, आज हमारे देश की एक-तिहाई आबादी गरीब है। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए फाइनली मैं आपसे यही कहना चाहता हूं और मेरी आपसे यही गुज़ारिश है, मैं सोच रहा था कि अगर मुझसे पहले सरकार की तरफ से कोई यह बात नहीं बोलता, तो मैं स्वयं ही यह बात बोलता कि बहुत अरसे के बाद पहली बार **...(व्यवधान)...**

MR. DEPUTY CHAIRMAN : Please conclude.

SHRI SITARAM YECHURY : I am concluding, Sir. बहुत अरसे के बाद पहली बार एक मुद्दे पर, जो हमारे देश की जनता के लिए एक बहुत ही ज्वलंत मुद्दा है, उस पर बहस करने के लिए सरकार ने पहली बार में ही मान लिया, यह एक बहुत अच्छा काम हुआ है। यह एक नयी परम्परा है और हम चाहते हैं कि सरकार इसको बरकरार रखे, ताकि संसद आराम से चल सके। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए सरकार से हमारी यही गुजारिश है कि हमारे सुझावों पर थोड़ा ध्यान दें और इनको लागू करने की कोशिश करें। धन्यवाद।

SHRI KALPATARU DAS (Odisha): Mr. Deputy Chairman, Sir, the issue now debated and discussed in this House is being discussed in each village and in each poor family in the country. Sir, this is not limited to price rise and the essential commodities or foodgrains. There has been price rise in respect of all the items required for infrastructure and other items required for day-to-day life. The Government took over hardly one-and-a-half months back. It is not expected that a Government can tackle price rise within one month or two months or even five months because price rise has become a regular phenomenon for years together. But, the intention of the Government must be clear. People should believe that the Government is determined to check price rise. Revising railway fares and freight charges just before convening this Session of Parliament does not speak about the intention of the Government that the Government is keen to reduce prices. The Government has come to power with a promise that good days are coming. If good days are coming, price rise is a very important issue. The Government must have thought over it as to how to check price rise if they come to power. They have not thought about it and made such a promise to the people of this country. Now, they have accepted it, on the first day on the first issue when the Opposition raised the price rise issue, the Government accepted that they were prepared to discuss it. If the Government is prepared to discuss this issue, Government must be

[Shri Kalpataru Das]

very clear as to how they are going to tackle price rise in future. Amending the Essential Commodities Act will not solve the problem. Who are providing onions and potatoes? In the meeting of Ministers, it has been decided that onions and potatoes will be brought under the purview of the Essential Commodities Act. It will be a cognizable offence. Who are selling these in the villages? Total investment of sellers is hardly ₹ 3,000, ₹ 4,000, ₹ 5,000, these small shopkeepers are selling them in villages. If you go on arresting them and putting them under trial, this will not solve the problem of price rise. There should be a detailed discussion. The people in the Opposition should be taken into confidence. Mr. Yechury gave some tips and some solutions in this House. It can be discussed in different forums and a method should be developed to find out ways and means to check price rise. By just saying that we will do it will not solve the problem. Hoarding issue is mentioned here. Taking action for stopping hoarding is the duty of the State Government. You are creating a situation whereby price is rising like revision of railway fares. The State Government just cannot tackle the situation in this way. It is you, this Government, the BJP, who has promised good days for the people. You should find out and develop a method as to how to check price rise in a time bound manner. As some Members from that side have said, 40 paise hike in diesel price is not a hike. Can they assure us that during the next five years, the Government will not revise diesel price or petrol price any more? In a democratic way, the Leader of the House has said that he is accepting the demand of the Opposition immediately. In a similar way, he should tell us that after the Budget presentation there will not be any hike in the prices of essential commodities. The day, on which the Government took a decision to Convene the Budget Session, on the same day they took another decision on promulgating an Ordinance. This is undemocratic. The Government should take the House into confidence. At least, before convening the session of the House they should not have taken any unilateral decision. Just two or three days before the presentation of the Railway Budget, the Government has announced a hike in passenger fares and a hike in freight. This does not give a good signal. I hope the Government will come clear on this. Today, while replying to the debate, the Government should give a clear indication as to how they are going to tackle the price rise in future, not by telling us that this is a regular phenomenon, this is going on since a long time. This was not the assurance given by the Government in their election campaign and manifesto. They have received the mandate because they have promised to check the price rise. I expect the Government to come very clear on this and take the House into confidence. The Government should assure us that within a stipulated period of time they will check the price rise. Thank you.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Thank you very much. Now, Mr. Y.S. Chowdary.

SHRI Y.S. CHOWDARY (Andhra Pradesh): Mr. Deputy Chairman, Sir, it is very unfortunate that the age-old Congress Party has raised this issue. It is nothing but a self-goal. They have been in power for ten years. What were they doing to check the price

rise? What they have done during that period was 2G, 3G and corruption issues which have taken care of the cash flows. Now, the present Government has not yet completed forty days. That means less than one per cent of the period which they have governed. By asking this question, they have made themselves a laughing stock. They should not have raised this point at this point of time. In the last four years, our Telugu Desam Party had been raising the issue of price rise, but the previous Government did not bother to reply to our point. They have governed this country in an autocratic manner. They have taken every decision in this manner. So, the result of that is price hike on every commodity, on vegetables, on crude oil and rupee devaluation. It is because of 10 years of misrule of the UPA Government. It is very unfortunate that they have failed in every field. That is the result of this price hike. They should not have asked this question. This is nothing but a self-goal. Thank you.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Thank you, Mr. Chowdary for being brief. Now, Shri Praful Patel. Mr. Chowdary's good example can be followed.

श्री प्रफुल्ल पटेल (महाराष्ट्र): उपसभापति महोदय, अभी हमने महंगाई पर चर्चा करने के लिए प्रश्नकाल को स्थगित किया और माननीय नेता, सदन ने इस बात को स्वीकार किया, इसके लिए मैं उनको बधाई देता हूं। उन्होंने एक अच्छी परम्परा की शुरूआत की है। केवल विरोध के लिए विरोध करना, यह हमारा मकसद नहीं है, लेकिन जिंस उमग और उत्साह के साथ लोगों ने आपको इस जगह पर लाकर बिठाया, उसमें लोगों की अपेक्षा और लोगों की आशा बहुत ज्यादा जागृत हो चुकी थी और लोगों को यह लगा था कि आपके आते ही आपकी जादू की छड़ी घूमेगी और लोगों की सारी समस्याओं का निवारण हो जाएगा। प्रधान मंत्री जी ने अपने ब्लॉग में ही कहीं लिखा, मैंने सुना और अभी देरेक जी भी हनीमून की बात कह रहे थे कि मुझे तो हनीमून करने का भी वक्त नहीं मिला, उसके पहले ही मेरा हनीमून समाप्त हो गया। अच्छी बात है, आपको यह जागृति बहुत जल्दी आ गई और आपकी समझ में यह आया कि देश का जो ढांचा है, उसमें देश को चलाने के लिए कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है और एकाएक आपके पास भी कोई ऐसी कमियां नहीं है जिससे कि आप इन समस्याओं को कल के कल हल कर पाएंगे।

आजकल आप टेलीविजन तो ज्यादा ही देखते होंगे, क्योंकि आपको 10 तारीख को बजट प्रस्तुत करना है। मैं कल रात को ही एक चैनल पर देख रहा था कि एक पुराने कॉलेज, जहां से आपने ग्रैजुएशन किया, वहां के बच्चों से यह पूछा जा रहा था कि आप अरुण जी से क्या एक्सपेक्ट करते हैं, आप इस सरकार से क्या एक्सपेक्ट करते हैं। इसका वे लोग जो जवाब दे रहे थे, वे बड़े इंटरेस्टिंग थे और जो आपके लिए भी मैं समझता हूं कि थोड़ा-बहुत चिन्तन से ज्यादा चिन्ता का विषय बनेंगे कि इतनी ज्यादा अपेक्षाओं को आप कैसे पूरा करेंगे। हम मुम्बई, महाराष्ट्र से आते हैं। आपने जिस दिन रेल के किराए बढ़ाए, मुझे मालूम है, प्रकाश जी और हमारे गीते साहब, ये बहुत अच्छे से जानते होंगे कि एकाएक लोगों की भावना कितनी तीव्र हो गई। लोगों में आपके बारे में जो एक उत्साह था, वह किस तरह से एक गुस्से में परिवर्तित हो गया। इसलिए, आगे बहुत सारी चुनौतियां आपके सामने हैं।

आज ही अखबार में योजना आयोग के बारे में एक खबर आई है। उस वक्त मैंने लोक सभा में इस बात का विरोध किया था, जब उन्होंने गरीबी-रेखा के नीचे के कटऑफ श्रेणी को 27 रुपये बताया था।

[श्री प्रफुल्ल पटेल]

उस वक्त इसका पूरे देश ने मजाक उड़ाया था, सभी पार्टियों ने उसका विरोध किया था और उस वक्त भले ही हम सरकार में थे, लेकिन हमने कहा था कि योजना आयोग के ये आंकड़े सरासर गलत हैं। उस वक्त 27 रुपये में किसी को गरीबी-रेखा के नीचे गिनना और आज के आखबार में 45 रुपये या 33 रुपये, इस तरह का एक आंकड़ा आया है। हो सकता है कि आप कहें कि यह कमिटी हमने नहीं बनाई, यह पहले की कमिटी थी। खैर, ऐसी तो बहुत सारी चीजें हैं, जिन्हें पहले की सरकार ने किया और उनका श्रेय आज आप ले रहे हैं, वह अलग बात है, लेकिन उसके बावजूद मैं यह कहना चाहूंगा कि आपको 45 रुपयें या 33 रुपये मंजूर हैं या नहीं, इसका भी तो आपको कहीं न कहीं स्पष्टीकरण करना होगा। अगर वह आपकों मंजूर नहीं है, तो इस देश के गरीबों की किस तरह से परिभाषा होगी, उनकी क्या डेफिनिशिन होगी, इसका भी आप स्पष्टीकरण करेंगे, क्योंकि लोग जानना चाहेंगे। बी.पी.एल. और ऐसी कई योजनाएं सरकार की हैं, जिनके जो लोग लाभार्थी बनते हैं, वे इस कटऑफ फ़िगर के बाद लाभार्थी बनते हैं। Who is BPL यह डेफिनिशन होने के बाद ही बहुत सारे लाभार्थियों को उसका लाभ मिलता है। सरकार की ऐसी कोई योजनाएं हैं, चाहे वह आवास योजना हो, चाहे वह खाद्य पूर्ति की योजना हो या ऐसी अन्य योजनाएं हों, जो सरकार की वेलफेयर स्कीम्स हैं, उनका लाभ उस कटऑफ के बाद ही मिलता है। इसलिए कहीं न कहीं इसका आपको भी स्पष्टीकरण करना पड़ेगा कि आप इस डेफिनिशन को किस तरह से गिनना चाहते हैं, वरना मैं समझता हूं कि आप चाहे कितना भी कहेंगे, वह लोगों की सारी अपेक्षाओं के ऊपर पानी फेरने जैसी बात होगी।

अभी यहां अलग-अलग लोगों ने बहुत सारी बातें कही हैं। अभी यहां प्याज़ और आलू की बात हो रही थी। प्याज़ और आलू, इसका रास्ता आप लोगों के लिए भी कोई बहुत आसान नहीं है। आप केवल कहेंगे कि हमने इसको में Essential Commodities Act में ला दिया, तो इसलिए होर्डिंग की क्या डेफिनिशन है? इस पर कई लोगों ने सवाल उठाए, इसलिए मैं उन पूरी बातों को दोबारा नहीं बोलूंगा, लेकिन यह डेफिनिशन कोई आसान नहीं है। हम महाराष्ट्र से आते हैं। अगर नासिक और लासलगांव में, जहां इस इस देश के 30 प्रतिशत प्याज़ का उत्पादन होता है, वहां के किसान का दाम जब घटेगा और वहां पर जब दूसरी आवाज उठेगी, तो उसके लिए आपके पास क्या जवाब है? इसके बारे में आपको सोचना पड़ेगा। आप कहेंगे कि शहरों में लोग महंगाई की बात करेंगे, तो दूसरी ओर जहां आज 30 परसेंट उत्पादन होता है वहां का किसान भी इस देश का नागरिक है, उसको भी प्याज के आलावा बाकी सब चीजों को खरीदना पड़ता है। उसकी जब आमदनी कम होगी और उसकी बाइंग पॉवर कम होगी तो उसका उपाय क्या होगा, यह भी सोचना पड़ेगा। अभी जो आपने एम.एस.पी. बढ़ाई, केवल 50 रुपया एक पैडी पर, व्हीट पर, राइस पर आपने एम.एस.पी. बढ़ाई। पवार साहब, यहां बैठे हैं। पिछले साल 80 रुपए एम.एस.पी. बढ़ी। मैं लोक सभा में जिस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता था, उस क्षेत्र के लोगों ने और उससे लगे हुए छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के मुख्य मंत्रियों ने भी आपके पास निवेदन किया है कि हमारे यहां यह बोनस जो कम देते हैं उसकी वजह से जो प्रोक्योरमेंट की एफ.सी.आई. की जो प्रक्रिया है, उसको घटाया न जाए। चूंकि आप उतना प्रोक्योमेंट नहीं कर पा रहे हैं तो बहुत सारी चुनौतियां आपके सामने आगे आने वाले दिनों में आने वाली हैं। महंगाई के बारे में आप जो कहते हैं, अगर महंगाई की बात करते हैं, किसानों की बात करते हैं तो उसी तरह से फर्टिलाइजर के दामों का क्या होगा, पेस्टिसाइड्स के दामों का क्या होगा, ये सारी चीजें भी महंगाई का एक पार्ट होती हैं। अभी कुछ समय पहले पेट्रोलियम मिनिस्टर बैठे थे, मैं उनका कही इंटरव्यू देख रहा था। उन्होंने कहा कि फिलहाल नहीं, तीन महीने बाद, चार महीने बाद हम सोचेंगे। मतलब महाराष्ट्र और अन्य राज्यों में चुनावों के बाद हम निश्चित भाव बढ़ाएंगे। इसमें कहीं दो राय नहीं है, यह आपने संकेत दे दिया है।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Now please conclude.

श्री प्रफुल्ल पटेल : इसलिए रेल किराया हो, या डीजल, पैट्रोल के दाम हों, चाहे ये सारी चीजें जो अभी आप कह रहे हैं, अब इराक की समस्या के बारे में आपने कहा स्वाभाविक है। लेकिन हमारी सरकार भी तो यही कहती थी कि अंतर्राष्ट्रीय तेल के दाम अगर बढ़ते हैं और जिन कारणों से बढ़ते हैं, वे भारत सरकार के अधीन नहीं है, हम लाचार हैं क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियां कुछ अलग हैं। तब तो आप कहीं आकर कहते थे कि बिल्कुल नहीं, यह तो सरासर गलत है। अभी जब सीताराम जी ने कहा कि पैट्रोलियम कम्पनियों का जो मुनाफा है उसको घटाकर अगर लोगों को उसका लाभ दिया जाए, आपके माध्यम से भी यह प्रश्न उठाया गया था। मुझे आपका भी स्मरण है, आपने भी कहा था कि जो टैक्सेशन होता है उसके ऊपर, जो ड्यूटीज लेवी होती है on the prices of petroleum products, इसको हम घटाकर हम उसका लाभ लोगों को देंगे। जरूर दीजिए, अच्छी बात है। But there is going to be a strong issue before you to manage the fiscal deficit on the one side and, on the other side, to meet people's expectations. I know, Arunji, you are a very erudite person, and I don't want to go into too much of details. लेकिन एक बात निश्चित है कि अभी 45 दिन हुए, 26 मई को प्रधान मंत्री जी और आप सब ने शपथ ली।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Prafulji, please conclude.

श्री प्रफुल्ल पटेल : और उस दिन से आज 45 दिनों में आपने कितनी चीजों के अगल-अलग तरीकों से दाम बढ़ाए, चाहे पैट्रोलियम पदार्थों के हों या रेल के हों या अन्य चीजों के हों। जो-जो आरोप आपने पिछले सरकार पर लगाए, उसी रास्ते पर आप चलने के लिए ऐसा कर रहे हैं। और इसलिए two wrongs don't make a right. हमनें गलती की इसलिए हमने भी उसी परम्परा को आगे बढ़ाया, यह कोई आपके लिए कोई बहुत सुखद संकेत नहीं हैं। इसलिए कृपा करके इस देश के सर्वसामान्य लोगों के लिए और मध्यमवर्गीय लोगों के लिए आप कोई उपाय या योजना लाने का काम करिए और देश में महंगाई और लोगों की जो बड़ी-बड़ी अपेक्षाएं बनी हुई हैं, इनकी पूर्ति करके के लिए आप जल्द से जल्द कोई चाणक्य नीति को अपनाने का काम करिए। (समाप्त)

SHRIMATI KANIMOZHI (Tamil Nadu): Sir, people had a lot of expectations when the new Government came into power, and today, they are in for a big shock with rise in prices, with rail fare hikes, and with prices of petrol, diesel, LPG, etc. going up. People are really shocked. And they did not expect this. And it has a cascading effect on the prices of all other items in the country today. It is the common man, the farmers, the people from below poverty line, who are really affected by the rise in prices. When the Government came into power, and even during the elections, they were campaigning about the common man, and they promised that it would be one of change. But nothing has happened. It is just that people are really disappointed about what has happened now.

Everybody here has spoken about petrol, diesel, LPG prices and rail hike. So I would like to bring to the notice of the Government, especially, the problems facing the agricultural sector. There is no clear policy to protect the farmers and there are no storage facilities. Most of our products, the vegetables, the fruit and the foodgrains, are wasted

[Shrimati Kanimozhi]

in this country. Nearly half of what has been produced goes waste. It does not reach the markets because we do not have proper storage facilities in this country. Of course, coming from a State like Tamil Nadu, we are always faced with problems like water crisis. We do not have a clear policy about water management in this country. The linking of rivers has been discussed many times but nothing has happened, nothing has been taken forward for linking of rivers so that it could be made possible for every State to go ahead with agriculture because water is a major problem in many of the States and if affects agriculture and we have to think of bringing down the production cost of agricultural produce. In most of the countries when prices go up, the farmer benefits, but in India it is not the farmer who benefits when the prices of agricultural products goes up. The farmer does not benefit in any way. It is only the middlemen, it is only the hoarders, it is the others in-between the consumer and the farmers who benefit. The farmer does not get any benefit and the Minimum Support Prices are so low that the farmer cannot benefit. Most of them give up farming; they move away from the villages and the next generation is not prepared to take up farming. So, there is actually no protection for agriculture and farming in this country. That has to be really taken into consideration. Of course, the products reach the market; the products reach the common man. In Tamil Nadu, during the DMK Government, we had this scheme called The Farmer's Market, 'Uzhavar Santhaigal' where the farmers could come and directly seil their products to the consumers. In this Government, of course, it is not being followed but still it is a project which can be taken into consideration countrywide, when the farmer actually can meet the consumer and sell their products directly. This can be thought of as a project which should be brought about in the entire country so that it can help the farmers throughout to sell their products without middlemen, without people in-between the consumer and get a good price for their produce. In this scenario, it is the consumers and the farmers who are really being affected and there is a Tamil song which was written by Pattukkottai Kalyanasundaram, *"Kadu Velanjenna machan, namakku kaiyum kalum thane micham"*. It roughly translates as to what is the gain even if the land yields a lot. Finally, it is only our empty limbs that remain. That is the state of the farmer today. We have to get most wholesome policy, a policy which actually benefits the farmer. And the farmers should be guided. If the prices of onions go up, then all the farmers want to produce onions and after three months the prices come down because everybody has produced onions. There is a surplus in the market. So there should be guidance as to what should be produced because in every other country, in many of the developed nations, every land is being taken into account, is being taken into consideration. They are scientifically measured, how much of produce it can yield, what kind of crops have be to sown over there and what kind of fertilizers should be used. Everything is measured and the yield is really high. Sir, in spite of so much land being used for agriculture in India, our yield is very, very low, because our scientific methods are not reaching the farmers. The major problem in the country is that our farmers are not being protected. So, unless an appropriate

policy is put in place which reaches to the farmer, it is going to be very difficult to control the food prices. Thank you.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: The discussion will continue after the lunch break.

The House is adjourned to meet at 2.00 p.m.

The House then adjourned for lunch at one minute past one of the clock.

The House reassembled after lunch at two of the clock,

MR. DEPUTY CHAIRMAN in the Chair.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Now, we will continue with the discussion on price rise and inflation. Shri Anil Desai to speak.

SHRI ANIL DESAI (Maharashtra): Sir, thank you very much for the opportunity to speak on the very important issue of inflation. It is a matter of concern for one and all in the country. The spiralling prices of the essential commodities, food grains, have gone through the sky. Really, it has broken the backbone of the common man. Very distinctly, the way the print media has come out with various headlines that are being hit every day, even in the morning newspaper itself, the definition of poverty, the definition of poor is being changed. Very distinctly, in the last couple of days when headlines were there on pictures of tomato, pictures of carrot and various other vegetables mentioned with a kind of comparative chart which was given comparing the prices of yesteryears and what the prices were a few months back. This has really shattered and shaken the psyche of the common man, the medium middle-class. This problem of theirs needs to be addressed by the Government. If you really see into the reasons, it is not the governance of the last forty days what the NDA Government has been doing, but whatever has happened is a cumulative effect which happened since the UPA Government's regime. It is the failure of the UPA Government's regime, literally on every front, that has caused a fall in the GDP. We have seen the economic slow-down, we have been witnessing the stunted growth. This is why the price rise and other factors are being faced by the common man and the people of India.

Rising prices of diesel, petrol, cooking gas, etc., have affected the transport. Of course, that has again given a boost to the price rise. If you happen to see the reasons behind that — whatever is happening in the Middle East, lraq — again, as Shri Sitaram Yechury had pointed, deregulation of the price in petroleum and petroleum products has also added to this. Now, on the prices of rice, potato, onion, tomato, cereals, milk, bread, fruits, etc., the way things are happening, this is an issue which needs to be addressed. It was spelt by the earlier Governments also, but real focus is being given by the dynamic leadership of Narendra Modiji under the NDA Government to deal with hoarding, hoarders

[Shri Anil Desai]

and elimination of middle-men. The distribution of the produce from farms directly to the ultimate consumer will be the order of the day the Government is contemplating. They are coming out with a revised scheme, which should be taken into account. During the UPA Government, in its regime, the way scams were taking place, policy paralysis was the main cause. There was indecisiveness on the part of the Government in various departments like the ones that deal with infra-projects and power projects. That has weakened the economy to a great extent and if the health needs to be restored back, if it is to be given momentum, that will require some time. But, at the same time, we just can't endorse what is happening today, what is the situation of the common man today. At the same time, we need to realise that unemployment is a big problem and it should have been' addressed, and it should have been the order of the day. The UPA Government failed on that count. Sir, the MNREGA Scheme would have given a real boost to the rural areas and the poor people of India, but it has not served the purpose. Similarly, encouragement should have been given to the public sector, but the situation prevailing today in the public sector' needs to be addressed. I was there On the Committee on Public Undertakings where the matter was largely debated about the FCI godowns and its conditions where food is really rotting, and a significant part of the food grains which is produced in the country by the farmers is not stored properly. We do not have that kind of facilities which need to be given. I think in the new Government, under the leadership of Modiji, it is happening.

As regards the failure of monsoon, I mean, the danger which we are facing, it is one of the main reasons for spiralling prices of commodities and the prices of agro products also. That is the reason why the budgets of the households are really rising in a big way. But the NDA Government, under the leadership of Modiji, is coming up, and this problem will be taken up on the lines of disaster management plans, and the Government will deal with the problem of drought.

Sir, in Maharashtra, under the UPA Government, the things are not good. There is failure of the Agriculture Department especially. There are scams which took place in the Irrigation Department. A scam of more than ₹ 70,000 crores was detected in the Irrigation Department. A question about it was raised on the floor of the House and was debated very hotly throughout Maharashtra. But the unfruitful expenditure which was done under irrigation projects yielded 0.01 per cent of additional land which came under irrigation. It was a big jolt for the farmers of Maharashtra who were really left high and dry, and this issue was not addressed by the Maharashtra Government as of date. This has again added to the rising costs.

Sir, when the railway fare hike was declared, ...*(Time-bell rings)*... When the railway fare hike was declared, a big uproar was there; resentment was there in Mumbai also. But, understanding the emotions, and understanding the plight of the people, immediately the NDA Government rolled back the prices. ...*(Time-bell rings)*... The real aim to hike the fares was to give international class travel to the people of the country.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please conclude.

SHRI ANIL DESAI: But sensing the uproar from the people, the hike was rolled back. Sir, lots of issues will be taken up by the NDA Government, and the slogan of अच्छे दिन आने वाले हैं will come true, and, naturally, they are dealing with it on a war-footing. The NDA Government will be resolving the problem of price rise to the ultimate satisfaction of the people of India. Thank you very much, Sir.

सरदार सुखदेव सिंह ढिंडसा (पंजाब): धन्यवाद उपसभापति महोदय, सबसे पहले तो मैं, लीडर ऑफ द आउस ने जो परम्परा आज शुरू की है, उसके लिए उन्हें बधाई देना चाहता हूं। सभी ऑनरेबल मेंबर्स को चाहिए कि ऐसी परम्परा को जारी रखें। पिछली सरकार में सभी मेंबर्स देखते थे, आप भी चेयर पर बैठते थे और आप भी देखते थे कि कई-कई दिन हाउस चलता ही नहीं था क्योंकि डिसकशन के लिए जब सरकार न कह देती थी तो कुदरती हाउस एडजर्न हो जाता था, लेकिन आज उन्होंने एक बहुत बच्छी परम्परा शुरू की है। मैं समझता हूं कि यह एक शुभ दिन है। दूसरा, जब भी किसी चीज़ की कीमत बढ़ती है - अब तो बहुत कुछ बढ़ गया है - तो हर आदमी को और हर पार्टी मेंबर को चिंता होती है, इसमें कोई शंका नहीं है। लेकिन चूंकि इसका बहुत अधिक असर गरीब पर पड़ता है, इसलिए सभी को उसके लिए चिंता होती है। आज सभी ऑनरेबल मेंबर्स ने, चाहे वे रूलिंग पार्टी के हों या अपोज़िशन के हों, इस पर चिंता जाहिर कही है। मैं भी अपनी पार्टी और अपनी तरफ से इस संबंध में चिंता जाहिर करता हूं, लेकिन साथ ही साथ यह बात भी कहना चाहता हूं कि अभी सरकार को बहुत कम दिन मिले हैं। यह ठीक है कि मोदी जी की सरकार ने बहुत सारे वायदे किए हैं, जिनके बारे में कई मेंबर्स ने कहा है कि वायदे तो बड़े-बड़े किए, लेकिन यह बात भी ठीक है कि कोई जादू की छड़ी तो है नहीं कि एक-दो महीने में ही सब कुछ ठीक हो जाएगा। फिर भी पूरी कोशिश हो रही है कि महंगाई को कैसे रोका जाए। मैं यह कहना चाहूंगा कि जितनी देर होर्डर्स को, बिचौलियों को आप नहीं रोकते, उनके ऊपर सरकार पूरा शिकंजा नहीं कसती, उतनी देर तक इस पर कंट्रोल नहीं हो सकता। कई मेम्बर्स ने एग्रीकल्चरिस्ट के बारे में कहा है। आप देखिए कि जो किसान सब्जी उगाता है, वह उसे किस भाव पर बेचता है और मार्केट में वह किस भाव पर बिकती है। अगर आप इस पर कंट्रोल नहीं करते, तो यह महंगाई रुक नहीं सकती है। इसलिए मेरी सरकार से अपील है वह उन होर्डर्स को, उन बिचौलियों को रोके। यह बताया जाता है कि फूड एक्ट आया है, उसके अनुसार जब तक इस देश में महंगाई नहीं रुकेगी। सरकार को इस दिशा में काम करना पड़ेगा। दूसरी बात किसानों की है। कई मेम्बर्स ने कहा है कि किसान को कुछ नहीं मिलता है। जो किसान सब्जी उगाते हैं, उनमें से कई किसान तो यह कहते हैं कि वे आगे से सब्जी नहीं उगाएंगे, क्योंकि वे जो सब्जी उगाते हैं, उसकी उनकी सही कीमत नहीं मिलती है, लेकिन मार्केट में उसका बहुत ज्यादा भाव होता है। सरकार को किसान का भी ध्यान रखना चाहिए और उसके लिए कुछ न कुछ करना चाहिए।

मेरी विनती यह है कि सरकार अभी थोड़े दिन पहले ही बनी है। मोदी जी ने लोगों से बहुत कुछ कहा है, ठीक है, चिंता भी है, लेकिन आपको उन्हें टाइम देना चाहिए। एक महीने में सारे देश का सब कुछ ठीक नहीं हो सकता, साल-छः महीने का समय तो उनको मिलना ही चाहिए। अगर उसके बाद भी ठीक नहीं होता है, तो हम इस पर कभी भी डिस्कशन कर सकते हैं। हाउस मो तो चलना ही है। इसको फिर कभी डिस्कस करिए, टाइम मिलने के बाद इस पर फिर डिस्कशन हो सकता है। आज सभी को चिंता है, हम भी इससे चिंतित हैं, लेकिन इस सरकार को टाइम जरूर देना चाहिए। एक बात रेल के किराए बढ़ाने की आई है। यह बात बिल्कुल ठीक है, मैं टी.वी. पर सुन रहा था, जब लोगों से पूछा जा रहा था, तो वे कह रहे थे कि चलो किराए तो बढ़ गए, लेकिन सहूलियत ठीक मिलनी चाहिए। मैं

[सरदार सुखदेव सिंह ढिंडसा]

सरकार से कहना चाहूंगा कि जो सहूलियतें हैं, जैसे रेलवे स्टेशनों की सफाई, रेल के डिब्बों की सफाई, इनमें सुधार होना चाहिए। रलवे में खाना-पान की सुविधा में सुधार होना चाहिए। सभी लोग ये कह रहे थे कि किराए बढ़ाने से हमें एतराज़ नहीं है, लेकिन सर्विसेज अच्छी नहीं मिल रही हैं। नई सरकार से लोगों को आशा बंधी है। मैं रेलवे मिनिस्टर साहब से कहूंगा, अभी तो उनका रेल बजट आना है कि आप इस तरफ ध्यान दीजिए। कुछ दिन पहले रेलवे मिनिस्टर ने कहा कि रेलें लेट नहीं होनी चाहिए, लेकिन मैं शताब्दी से चंडीगढ़ जाता हूं, वह कभी टाइम से नहीं पहुंचती है। अभी भी वैसा ही हाल है। इस बारे में मैं, उनसे कहूंगा कि इस पर पूरा कंट्रोल करना चाहिए क्योंकि अगर किराया बढ़ाया है, तो लोगों को अच्छी सर्विसेज मिलनी चाहिए।

डिप्टी चेयरमैन सहब, मैं एक बात जरूर कहूंगा कि कीमत बढ़ती है कुछ लोगों के कारण, कुछ लोग हैं जो उससे बहुत ज्यादा पैसा कमाते हैं। इसके बारे में मोदी जी ने कुछ स्टेप्स उठाए हैं, इसके बारे में सरकार ने कुछ स्टेप्स उठाए हैं, मैं सरकार से यही कहूंगा कि उसे और सख्त स्टेप्स लेने चाहिए ताकि जो बिचौलिया या होर्डर है, उसको सख्त सजा मिले, तभी यह काम रुकेगा। इतना ही कहकर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद

SHRI M. P. ACHUTHAN (Kerala): Thank you, Sir. This Government, the NDA Government, is insensitive to the problems, and plight of the common people of India. They are not conceding the fact that there is price rise. Our Prime Minister tweets daily on every issue, but not a single word on price rise is mentioned. They would not consider that price rise is affecting the common people of India. In one sense, the NDA Government has become an extension of the UPA Government — a third UPA Government — so far as the economic policies are concerned. This Government is continuing the same economic policies of the previous Government, which led to enormous price rise. Still they are saying that better days have come. Better days have come for whom? Better days have come only for the corporates, for the capitalists, for the big traders. Take the example of sugar price. The price of sugar has increased by more than ₹ 5 per kilogram. The Government has also given a grant of more than ₹ 4,600 crores to the Mill owners. Apart from this, the Government has also provided import-export subsidy. Still it is not being passed on to the sugarcane farmers, to the consumers. It is being passed on only to the factory owners. The situation is same in other sectors too. The UPA Government used to increase the price of diesel by 50 paise per month. The same policy is being continued by the present Government. They say that the public sector oil companies are running in loss. There is a latest draft report of the C&AG which says the total profit of the public sector oil companies in India has, in the past five years, reached more than 50,000 crores of rupees. It is being reported in the media. But the Government is still saying that the oil companies are running in huge loss. You want to decontrol petrol, apart from increasing the prices of LPG and kerosene oil. The question is whether this Government is ready to change the policies which have resulted in the increase of prices of all the essential commodities. Are you ready to check the prices of essential commodities? If yes, you will have to change your economic policy. You will have to ban the forward trading of essential commodities such as foodgrains. But

you are not ready for it. What instructions have you given to the State Governments? You have instructed the State Governments that there should not be any increase in the MSP of foodgrains; no incentives should be provided to the farmers. These directives will benefit the big traders, the corporates who are engaged in retail trade. They can purchase foodgrains at cheaper rates and hoard them. So, this Government is not serious about containing the rising prices and give relief to the people. If you are interested in containing the rising prices, you will have to universalize the PDS system. You have to provide all the essential commodities, onion and potatoes too, under the Public Distribution System. Are you ready for it? Then you can control the rising prices and provide relief to the common man. But you are not ready for it. You are just trying to curb the PDS. The previous Government talked much about the Food Security Act. But it has not yet been implemented. So, universalize the PDS system and provide all the essential commodities through the PDS at controlled prices, if you really want to control the rising prices. If not, mere saying 'better days have come' is not going to help. Of course, people believed you and voted for you. In the last elections, the people of India voted in your favour only because they wanted a change, a change in the policies of the then UPA Government. But you are still continuing with the same policies. If you are not ready to change, the same adverse effects would keep on haunting you and you will meet the same fate. Thank you.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Now, Shri Pramod Tiwari. Not here. Then, Shri Motilal Vora.

श्री मोती लाल वोरा (छत्तीसगढ़) : माननीय उपसभापति जी, मुझे इस बात को कहने में बहुत अफसोस हो रहा है कि एन.डी.ए. की सरकार ने एक महीना, इक्कीस दिन के अंदर जिस प्रकार से महंगाई को बढ़ाया है, उस महंगाई के बढ़ने से आम आदमी त्रस्त हुआ है। हमारे विपक्ष के नेता, श्री गुलाम नबी आजाद ने विस्तार के साथ सारी बातों का उल्लेख किया है और मैं समझता हूं कि उन सारी बातों को दोहराने की आवश्यकता नहीं है। आपने लोगों को बहुत सब्जबाग़ दिखाए, आपने बहुत उम्मीदें जगाईं, लेकिन आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि बजट पेश होने से पहले रेल किराये में भारी वृद्धि हो। रेल किराये में भारी वृद्धि होने का मुख्य कारण क्या है और उसका असर किस पर पड़ सकता है? रेल भाड़े और खाद्य पदर्थों की कीमतों में वृद्धि हुई है। हमारे खाद्य मंत्री जी बैठे हैं, उनका कहना है जो जमाखोर हैं, जो होर्डर्स हैं, उनके कारण भावों में वृद्धि हो रही है। आप बहुत कुशल मंत्री रहे हैं। मुझे उम्मीद थी कि आपके आने के बाद जिस प्रकार से खाद्य पदार्थों - दाल, चालव, गेहूं और तेल की कीमतों में वृद्धि हुई है, यह किस पर असर डालने वाली है? यह असर डालने वाली है आम जनता पर। यह उस आम जनता पर, जिस आम जनता ने आप पर बहुत भरोसा किया, बहुत विश्वास किया, असर डालने वाली है। आपने इस जनता के साथ विश्वासघात किया है, आपने जनता को छला है। आपने उनको बहुत अच्छे सपने दिखाए। आपने लोगों को दिन में तारे दिखाने की कोशिश की, लेकिन उन तारों को दिन में तो देख नहीं सकते, इसलिए आखिर में हुआ? आज आम आदमी त्रस्त है। हर आदमी इस बात को कहने के लिए मजबूर है कि इतनी बड़ी महंगाई की मार किसी भी सरकार के आने के बाद नहीं पड़ी। विपक्ष के माननीय नेता ने इस बारे में सारी बातें कही हैं, मैं उन बातों को दोहराने की आवश्यकता नहीं समझता हूं, लेकिन एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि यह सरकार वादों की सरकार

[श्री मोती लाल वोरा]

है। वादों को पूरा नहीं करने वाली इस सरकार को हमने पूर्व में भी देखा है। इन्होंने जनता के सामने बहुत से वादे किए थे। रेल भाड़े की वृद्धि ने आम आदमी की कमर को काफी झुका दिया है। मैं यह नहीं कहूंगा कि कमर को तोड़ दिया है, पर इन्होंने उसको और झुकाया है। रेल यात्री रेल किराये में वृद्धि के कारणा एन.डी.ए. का जो एलायंस है, शिव सेना के लोगों द्वारा और देश भर में जिस प्रकार के उग्र प्रदर्शन हुए हैं, वे इस बात का संकेत देते हैं कि दरअसल सरकार ने बिना सोचे-समझे यह कदम उठाया है। इतनी जल्दी कोई पहाड़ गिरने वाला नहीं था। पहले बजट पेश होता और आप बजट में यह वृद्धि करते, तो उसकी कोई आलोचना नहीं होती, लेकिन मालूम नहीं आपने क्या सोचा। आपने सोचा कि बजट पेश करते समय हमें लोगों की आलोचना का शिकार होना पड़ेगा, इसलिए आपने उससे कम दस-पंद्रह दिन पहले ही इस प्रकार की योजना को बनाया है। मैं समझता हूं कि इससे लोगों को बहुत निराशा हुई है। आपने शक्कर, दाल, तेल और प्याज के दाम बढ़ा दिए। आपने लोगों से बहुत वादे किए थे कि हम प्याज के भाव, आलू के भाव कंट्रोल कर लेंगे। ये भाव कहां पर कंट्रोल हुए? मैं समझता हूं कि आज प्याज और आलू खरीदने में सभी को तकलीफ हो रही है। आज जिस प्रकार आम आदमी की आंखों में प्याज को देखते ही आंसू आते हैं, ठीक उसी प्रकार उस आदमी की जेब भी कटी है। आज सरकार किस मुंह से इस बारे में कुछ कह सकती है? हमें तो भरोसा नहीं है कि सरकार अपने वादों को, जितने वादे सरकार ने किए हैं, उन वादों को पूरा करेगी।

सरकार के द्वारा यह कहा गया कि हम कुछ कड़े निर्णय लेंगे। उपसभापति जी, कड़े निर्णय लेने का अर्थ यह तो नहीं होता कि कड़े निर्णयों का बोझ आम आदमी, गरीब जनता और जो गांव में रहने वाले लोग हैं, उन पर पड़े। अगर आप कड़े निर्णय लेते तो आप उन उद्योगपतियों के विरूद्ध ऐसे कड़े निर्णय ले सकते थे। लेकिन आपने ऐसा साहस कहीं पर नहीं दिखाया और साहस दिखाने की आपमें हिम्मत भी नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं कि आपको उन सबसे चुनाव के दौरान भारी सहयोग मिला। आज आप होर्डर्स की बात करते हैं। अगर आपने होर्डर्स के ऊपर छापा मारा होता, तो हरेक गोदाम में आपको चावल, दाल, गेहूं, चना, तेल, मिट्टी का तेल, शक्कर इत्यादि का बड़ा स्टॉक मिलता। आपने कहा कि हम स्टॉक को लिमिट करेंगे। आप इसे कब लिमिट करेंगे, आपने इसकी कोई मियाद तय नहीं की। मुझे लगता है कि सरकार अपने वादों मुकर रही है। सरकार के वादों को हम किस प्रकार नजरअंदाज कर सकते हैं? एसेंशियल कमोडिटीज़ के अंतर्गत आपने अमेंडमेंट की बात कही है। बहुत अच्छा होता, आप अमेंडमेंट लाते, लेकिन उसका फायदा किसको मिलता? फायदा मिलना तो दूर रहा, मुझे याद है कि सरकार ने कहा था कि बजट बनाने से पहले हम अपनी राज्य सरकारों से सलाह-मशविरा करेंगे। आपने सलाह-मशविरा जरूर किया होगा, अगर नहीं किया, तो करके देखें। आपने सलाह-मशविरा केवल विकास के मामलों को ध्यान में रख कर किया। क्या महंगाई के बारे में किसी भी राज्य सरकार को आपने विश्वास में लिया? आपने उन्हें विश्वास में नही लिया। यह आपकी चोथी घोषणा है। आपकी ऐसी घोषाणाएं, जिनका असर लोगों पर पड़ने से आज लोग परेशान हैं। हर दिन आदमी सोचता है, घर की महिलाएं सोचती हैं कि आपने कुकिंग गैस के दाम भी बढ़ा दिए। हमारे पेट्रोलियम मत्री जी ने कहा कि फिलहाल हमने तीन महीने तक **(समय की घंटी)** दाम रोक दिए हैं। अब तीन महीने के बाद, जब बजट सत्र समाप्त हो जाएगा, उसके बाद आप जिस प्रकार की बढ़ोतरी करने की बात कहेंगे, उसका आपके पास कोई जवाब नहीं है। अगर आपके पास जवाब हो, तो कृपया इस बात को बताएं। मैं तो समझता हूं कि...।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please conclude.

श्री मोती लाल वोरा : मैं केवल एक मिनट लूंगा। मैं केवल एक बात आपके सामने रखना चाहता हूं, जो आउटलुक में छपा है। Sir, I would like to read only one sentence from it. Hon. Deputy Chairman, Sir, I want to bring to your notice not more than one sentence. I quote, "Making an assessment of a government that is just about completing its first month in office is certainly bad form, and possibly unfair", which I also believe. "But as an intrepid watcher quipped this weak, when a 'marathon-runner chooses to do a 100 metres sprint' without warming up, questions are bound to arise." Questions have arisen and the Government has to reply properly on all the issues which we have raised or the LoP has raised and the other hon. Members raised. I think the Government has to reply. I do not hope that the Government would roll back all these prices. It is better for the Government to roll back all these prices immediately so that the people can have some faith in the Government. I do not know whether the Government has got any faith. The people of this country have lost faith in this Government within one month and twenty-one days. Thank you, Sir.

SHRI RAJEEV CHANDRASEKHAR (Karnataka): Thank you, Sir, for giving me this opportunity.

Sir, before we allow politics to derail the real focus on this issue, it is important to understand the real reasons for price rise and where we are as an economy. Sir, the situation with the economy and the perilous fiscal health of the Government is — more than anything else — driving this phenomenon of unrelenting inflation and price rise that is, in turn, making the lives of poor and middle class intolerable and adding miseries to the already difficult standards of living.

Sir, the economic situation we face today is most challenging. There is no avoiding this fact. In the reply to the President's Address, I referred to our economy as being on a fiscal precipice and left hanging there only because of some adept fiddling with numbers. Sir, we must understand the real story of inflation. Inflation and price rise has been on the up for almost 24 successive quarters, accompanied by GDP declines for the last 12 quarters. While inflation based on wholesale prices averaged 6.1 per cent during UPA-1, it was a percentage higher at 7.1 per cent in UPA-2. In the case of food inflation, the acceleration has been more pronounced, from 6 per cent to almost 12.2 per cent over the same period. And throughout this period, various functionaries of the Government would famously predict an imminent inflation moderation, to be proved wrong again and-again. So, to the critics of this Government, I would humbly point out that the number of promises made and broken by the previous Government on this issue are far too many to enumerate and describe, and I would not want to embarrass them by quoting any or all of them.

Sir, the problems for this trend of price-rise are structural issues with our economy that have been created over the last four-five years. The economy has been stuck in a low

[Shri Rajeev Chandrasekhar]

growth and high inflation mode for several years now causing many connected problems. Most of the reasons for this situation can be attributed to the ouf-of-control profligacy that has been unmatched in its size and scope over the last few years.

Sir, even to many who are expert economists — and I am not one of them; I am not an expert economist — the problem has always been one of supply-side constraints. This has been known for several years, but with hardly any real effort to solve it, as can be seen by lakhs of crores of projects that have been lying blocked over several years. The Chairman of the National Statistical Commission said, the main reason for mounting inflation was the then Government's failure to roll back the 2008 fiscal stimulus in time. This led to the economy overheating and prices firming up even as the Government failed to balance the food economy. The Economic Survey by the then Chief Economic Advisor, who was also the Prime Minister's Economic Advisor and now the RBI Governor, clearly pointed out the mistakes in the Government's stimulus policy in 2008. The easy strategy of creating more consumer demand, rather than equally driving investments to bridge the supply gap mismatch, had further accentuated the gaps that had been created by the easier economic strategy of fuelling a consumption economy without tackling the more difficult and hard work required, regulatory and policy issues required, for a sustainable investment-based economy.

Sir, there is no alternative to bringing fiscal responsibility and a value for money culture back into the Government. The current model of borrowing almost ₹ 50,000 crores a month is unsustainable and is placing liabilities on our future generations' heads. Public spending is notoriously leaky, fosters corruption, and worst, only a small percentage of those who worked for the targets are receiving this spending. Fundamental reforms are required in this area and are long overdue. A new approach to Government spending is necessary. Only then can Government borrowing be moderated. To add to this, poor regulation of commodity exchanges and poor enforcement of laws against speculators is another reason why prices are being fixed.

Sir, deep structural reforms are required in the agricultural and food economy. Apart from the ideas that are already with the Government, that of setting up special courts to stop hoarding, creating a price stabilization fund, making FCI more efficient by unbundling its operations, creating a National Agriculture Market and creating a concept of farmers' markets where farmers can sell directly to consumers are required.

Sir, as you can see from what I just described, the structural imbalances and problems created in our economy are deep and significant. These will take time to unwind and with reforms is needed a more effective economic strategy, a strategy of smarter, more effective Government spending to replace the profligacy of the last ten years, a focus on consumers and the poor, rather than business and friends and crony capitalists. Time is required for this Government to get the economy back in shape and implement these required reforms.

Sir, I end with this one suggestion for the Government — you must reach out to the people and communicate the reality to them. Make the rationale and reasons for the difficult decisions that are being imposed on people known transparently. As my friend Derek has said and my senior colleague Sitaram has said on repeated occasions, it would be difficult for people to blandly accept that PSUs and Railways are losing money and so people must accept hardship. This Economic Survey and the Budget must make it clear to the people the extent of economic problems we are in and the fiscal legacy that has been inherited by this new Government. If people are to bear hardship, they must know the reasons and for how long.

Thank you, Sir. Jai Hind.

श्री के.सी. त्यागी (बिहार): सर, मैं आपकी इजाजत से एक प्वायंट उठाना चाहता हूं। दोनों तरफ के जो माननीय सदस्य बहस में हिस्सेदार थे, मैं उनसे अलग कुछ कहना चाहता हूं। मैं आपके जरिए रामविलास पासवान जी को सम्बोधित करना चाहता हूं।

हम और वे किसानों के नेता जो चौधरी चरण सिंह थे, उनके साथ 30-35 साल रहे थे। पिछले 15 दिनों में इनके जो वक्तव्य हैं, उन्होंने मुझे बहुत कष्ट दिया है। इनके ही क्रियाकलापों से चीनी के दाम चार रुपये प्रति किलो अगले दिन ही बढ़ गए जिस दिन इन्होंने चीनी मिल मालिकों को छः लाख करोड़ रुपये का ब्याज मुक्त ऋण दिया। ब्राजील तथा दूसरे मुल्कों से चीनी आती है, उस पर 10 परसेंट के आसपास का जो टैक्स था, इम्पोर्ट ड्यूटी थी, उसको इन्होंने बढ़ाकर 40 परसेंट कर दिया। इसके अगले दिन ही बाजार में चीनी के दाम चार रुपये प्रति किलो बढ़ गए। वहां की जो रिपोर्ट्स हैं, वे यह हैं कि चीनी के दाम जितने ज्यादा बढ़ेंगे, चीनी मिल मालिकों को उतना ही मुनाफा होगा। पहले आपके थॉमस साहब थे, आधा नाश तो वे करके चले गए और अब बची-खुची कसर ये पूरी करने वाले हैं। मैंने इनका वक्तव्य देखा। ये राज्य सरकारों को धमकी दे रहे हैं कि जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस हम दिल्ली वाले तय करेंगे, खबरदार अगर एक नया पैसा भी किसी ने बढ़ाया, अगर बढ़ाया तो हम जिम्मेदार नहीं होंगे। अब दाल के, चावल के तथा अन्य चीजों के जो दाम तय हुए हैं, एम.एस.पी. तय हुई है, मैं इनको चुनौती देना चाहता हूं, सरकार को चुनौती देना चाहता हूं कि किसी इंडिपेंडेंट कमेटी से ये तय करा लें और अगर गन्ने का दाम 350 रुपये प्रति क्विंटल से कम होगा, तो मैं आपनी बात वापस लेने को तैयार हूं। पिछली बार इन्होंने गन्ने का दाम 218 रुपये प्रति क्विंटल तय किया था। अब गन्ने का टाइम आने वाला है। साढ़े ग्यारह हजार करोड़ रुपये आज सब्सिडी के रूप में देश के पूंजीपतियों को, लुटेरों को दे चुके हो, लेकिन उनमें से एक नये पैसे का पेमेंट किसानों को नहीं हुआ है। वे आत्महत्या कर रहे हैं। यह कैसी सरकार आई है? यह बात सही है कि कांग्रेस के हमारे मित्र कहते थे कि ये हमारे बताए हुए रास्ते पर चल रहे हैं। अगर ये उनके बताए हुए रास्ते पर चल रहे हैं तो फिर ये जल्द वहीं पहुंच जाएंगे जहां वे बैठे हुए हैं।

मैं तकलीफ के साथ यह कहना चाहता हूं कि एक तो इस बार तय हो जाए कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस किस चीज का क्या है। सुबह सीमेंट की बात उठी थी, स्टील की भी बात उठी थी। वे कौन लोग होते हैं, जो सीमेंट के तथा अन्य चीजों के दाम तय करते हैं? क्या अभी किसानों के संगठन, कृषि वैज्ञानिकों के साथ बैठ कर किसानों की जो फसलें है, उनके प्रोड्यूसेज हैं, उनके दाम तय होंगे? ऐसे ही थॉमस साहब कर के गए, 6000 करोड़ रुपये की सब्सिडी तो ये एस्मा के मालिकों को दे कर गए।

[श्री के.सी. त्यागी]

बाकी कसर हमारे मित्र रामविलास पासवान जी ने पूरी कर दी। मैं यह कहना चाहता हूं कि यह कैसी पॉलिसी है? आज से नहीं है, पचास साल की रस्में हैं। हम भी कई सरकारों में आगे-पीछे रहे हैं। यहां राज्यों में सरकारें चलाने वाले भी बैठे हैं। बसपा के लोग बैठे हैं, सपा के हमारे मित्र बैठे हैं। हमारी भी सरकार है। पंजाब के हमारे अकाली भाई बैठे हैं। हर साल हम और ये इकट्ठे आन्दोलन करते थे। मिनिमम सपोर्ट प्राइस के साथ-साथ बोनस दिया जाना चाहिए, क्योंकि यहां से किसानों को उनकी फसल का कभी ठीक दाम नहीं मिलता। उस पर भी रामविलास जी धमका रहे हैं कि खबरदार, अगर किसी ने एक नया पैसा भी दिया तो। तो दाम भी पूरे नहीं देंगे? मैं रामविलास जी से कहना चाहता हूं कि आप इतने पुराने साथी हैं, समाजवादी आन्दोलन से हैं, आप लिबरल-मॉडेस्ट पृष्ठभूमि से आए हैं, हमारे-आपके सवाल कोई अलग-अलग नहीं हैं, इसलिए एक बार कॉस्ट एंड प्राइस कमिशन को बिठाकर, अच्छे लोगों को बिठाकर, तय कर लीजिए कि किसान का क्या दाम बैठता है। पिछले साल बड़ी मुश्किल से 218 रुपये प्रति क्विंटल गन्ने का दाम था, दो-ढाई महीने तक एक भी पर्ची पर दाम नहीं लिखा गया। आप एस्मा के लिए बड़े चिन्तित हैं। चूंकि वहां से सभी पोलिटिकल लोगों को चंदा मिलता है। मैं यह सिर्फ आपको नहीं कह रहा हूं। किसानों के संगठन के प्रति आपकी संवेदना ही नहीं है, चूंकि वह चंदा देने लायक ही नहीं है। हां, उनके वोट्स चाहिए। चंदा आपको एस्मा से चाहिए और वोट्स किसानों से चाहिए। कांशीराम जी कहते थे- 'वोट हमारा राज तुम्हारा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा।' वही काम इन्होंने कर दिया है। मैं कहना चाहता हूं कि रामविलास जी, ऐसा मत करिए। आप मिनिमम सपोर्ट प्राइस भी कम तय कर रहे हैं और धमकी भी दे रहे हैं, इस तरह से ये चीजें नहीं चलती हैं। आपने एस.ए.पी. के लिए मना कर दिया। आपने किसानों को बोनस न दिया जाए, यह तय कर दिया। तो आप एक बार तय करा दीजिए, कृषि वैज्ञानिकों को बिठा लीजिए। जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस तय होता है और मैं आपका मेनिफेस्टो पढ़ कर सुना दूं। विद्वान लोगों ने लिखा है, सबसे विद्वान वहीं बैठे हुए हैं, जिनको मैं चिदम्बरम साहब से हजार गुना बढ़िया मानता हूं। मैंने पिछली बार भी कहा था। मेरा अंतिम वाक्य यह है कि एम.एस.पी. होगी प्लस फिफ्टी परसेंट...। अगर एन.डी.ए. की सरकार, भाजपा की सरकार आई, तो किसानों को दाम देगी। अब आप आ गए हैं, तो अपने वचन निभाइए। धन्यवाद।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Now, Shri Vishambhar Prasad Nishad.

श्री विशम्भर प्रसाद निषाद (उत्तर प्रदेश) : माननीय उपसभापति जी, आपने मुझे मूल्य वृद्धि व महंगाई पर बोलने का मौका दिया है, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। मैं अपनी पार्टी, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को बधाई देता हूं, अपनी पार्टी के नेता प्रोफेसर साहब को बधाई देता हूं, उन्होंने मुझे पहली बार राज्य सभा में भेजने का काम किया। मैं पहली बार राज्य सभा में आया हूं और मैं पहली बार बोल रहा हूं। मैं अपने उपनेता माननीय अग्रवाल साहब को बधाई देता हूं।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Mr. Nishad, there is one point. Your Party's Chief Whip came and specially requested to give you two, three minutes. So, please don't expect a long maiden speech. You can take maximum five minutes. This is a special consideration because his Chief Whip requested.

श्री विशम्भर प्रसाद निषाद : माननीय उपसभापति जी, देश भर में जो महंगाई बढ़ी है, उसका कारण यह है कि बजट आने से पहले सरकार ने रेल भाड़ा बढ़ा दिया, पेट्रोलियम पदार्थों के दाम बढ़ा दिए। इसको लेकर आज पूरे देश में आंदोलन हो रहा है। चुनाव के समय इन्होंने कहा था कि हम

महंगाई खत्म कर देंगे, लोगों को पक्के मकान देंगे, लेकिन आज महंगाई चरम सीमा पर पहुंच गई है। चाहे यू.पी.ए. की सरकार रही हो या एन.डी.ए. की सरकार रही हो, इन लोगों ने जनता को अच्छे सपने दिखा कर सिर्फ उनसे वोट लेने का काम किया है। यह काम कभी यू.पी.ए. के लोगों ने किया, तो कभी एन.डी.ए. के लोगों ने किया है। महोदय, यह खेल कब तक चलेगा? आज गांव का जो किसान है, वह तीन लीटर मिट्टी के तेल के लिए पूरे दिन राशन की दुकान पर डीलर के पास बैठता है। उसको आज तक बिजली नहीं मिल पाई है और तीन लीटर मिट्टी का तेल भी नहीं मिल पा रहा है' तो ये कैसे गरीब लोगों को अच्छे सपने दिखाएंगे और उनके लिए अच्छे दिन लाएंगे? आज सबके पास मोबाइल हो गया है, लेकिन मोबाइल चार्ज नहीं हो पा रहा है, क्योंकि गांव में बिजली नहीं है। आज महंगाई इतनी चरम सीमा पर पहुंच गई है। उनके पास बिजली नहीं है, पक्का मकान नहीं है, खाने की सुविधा नहीं है। किसान की उपज का मूल्य वर्ष में एक बार बढ़ाया जाता है, जब कि पेट्रोलियम पदार्थों के दाम एक महीने में दो-तीन बार, वर्ष में कई-कई बार बढ़ा दिये जाते हैं। इसलिए इसका भी एक पैमाना होना चाहिए कि जिस तरह से पेट्रोलियम पदार्थों के दाम या अन्य चीजों के दाम बढ़ते हैं, उसी तरह से किसान की उपज के भी दाम बढ़ें। जब किसान के पास फसल होती है, तब दाम कम रहते हैं और जब यही फसल व्यापारी के पास आ जाती है, उद्योगपति के पास आ जाती है, तो वही दाम बढ़ा दिए जाते हैं।

महोदय, मैं उदाहरण के रूप में यह बताना चाहता हूं कि जब माननीया विदेश मंत्री, श्रीमती सुषमा स्वराज जी विपक्ष में थीं, तो उन्होंने कहा था कि आश्वासन से पेट नहीं भरेगा, काम करना चाहिए। आज इन्होंने कहा कि अच्छे दिन आने वाले हैं, लेकिन ये अच्छे दिन कब आएंगे? अब तो लोग यह कहने लगे हैं कि हमारे पुराने दिन वापस कर दो, जो साढ़े चौदह परसेंट रेल भाड़ा बढ़ा दिया और महंगाई बढ़ा दी, उसको कम कर दो, हमारे पुराने दिन अच्छे थे। इस तरह से इन्होंने महंगाई बढ़ाने का काम किया है। आलू, फल, सब्जी, वगैरह के दाम जिस तरह से बढ़े हैं, यह बहुत चिंता का विषय है। जो बड़े-बड़े उद्योगपति हैं, जिन लोगों ने स्टॉक कर रखा है, उनके लिए उन्होंने सिर्फ इतना कहा है कि हम छापे मारेंगे, इन पर कार्रवाई करेंगे। इस तरह से ये केवल आश्वासन देने का काम कर रहे हैं, कार्रवाई कहीं नहीं हो रही है, क्योंकि उनके चंदे से, उनके पैसे से मीडिया को उन्होंने पूरा हाईजैक कर लिया था। जो भी चैनल खोलिए, उसमें आता था कि अच्छे दिन आने वाले हैं। इस तरह से नौजवान गुमराह हो गया। उनको कहा गया कि हम सबको रोजगार देंगे, अब नौजवान रोजगार की आस में है कि हम सबको रोजगार मिल जाएगा। जिसके पास मकान नहीं है, वह सोचता है कि मुझे मकान मिल जाएगा। आज महंगाई चरम सीमा पर है। आज हमारे रुपए का मूल्य गिर गया है और डॉलर की कीमत बढ़ी है।

आज प्याज के दाम चालीस परसेंट बढ़ गए हैं। जब किसान के पास प्याज था, तब तो इसके दाम कम थे। आज जब यही प्याज बड़े व्यापारी यानी स्टॉकिस्ट के पास आया, तो इसके दाम क्यों बढ़ गए? इसकी तह तक जाना चाहिए। इस पर केवल भाषण देने से काम नहीं चलेगा, बल्कि इस पर सख्त कानून बना कर उसको लागू करने से काम चलेगा। जब सरकार इसको लागू करेगी, तभी जाकर काम चलेगा। इसके अलावा, हम पूछना चाहते हैं कि आज देश में जो महंगाई बढ़ी है, उसके लिए सरकार ने क्या उपाए किए हैं? ये केवल लोगों की भावनाएं भड़काने का काम करते हैं। आज उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार है। ये राज्य सरकार से कहते हैं कि बड़े स्टॉकिस्ट्स पर नियंत्रण कीजिए। इनके जो बड़े-बड़े स्टॉकिस्ट्स दिल्ली, मुम्बई और कोलकाता में बैठे हैं, उन पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? ये केवल प्रदेश सरकार को कह रहे हैं।

[श्री विशम्भर प्रसाद निषाद]

माननीय उपसभापति महोदय, हम आपसे यह कहना चाहते हैं कि यह सरकार इस पर काम करे। इनके तो अच्छे दिन आ गए, सरकार के अच्छे दिन आ गए, इनके मंत्रियों के अच्छे दिन आ गए और इनके सांसदों के अच्छे दिन आ गए, जब कि किसानों के बुरे दिन आ गए। आज किसानों की प्रत्येक जिंस का मूल्य 500 रुपये से लेकर दो-तीन हजार रुपये तक घटा है। चाहे वह दलहन हो या तिलहन हो, उनके दाम घटे हैं और जब वही व्यापारी के पास आ गए तो उनके दाम बढ़ने लगे हैं, तो किसान बरबाद हो गया। वर्षा कम होने से, मूल्य वृद्धि होने से और इराक में हिंसा होने से आज महंगाई आसमान छू रही है।

माननीय उपसभापति महोदय, हम वित्त मंत्री जी से यह निवेदन करना चाहते हैं कि आपने आज सुबह जो कहा है, उसको करिए, नहीं तो यही जनता बिठाने वाली भी है और यही जनता उठाने वाली भी है। आज जनता ने आपको इनकी वजह से बिठाया है। कांग्रेस के लोगों ने ज्यादती की, इन्होंने इतना भ्रष्टाचार किया, इतनी बेइमानी की कि इनकी वजह से आप लोग आज वहां बैठे हैं। अगर आप लोग भी वहीं कृत्य करेंगे, तो आपको भी कुछ दिनों बाद जनता सत्ता से बाहर कर देगी। धन्यवाद।

श्री प्रमोद तिवारी (उत्तर प्रदेश): माननीय उपसभापति जी, मैं आपका आभारी हूं कि आपने देश की सबसे ज्वलंत समस्या पर मुझे बोलने का मौका दिया है। मैं आपसे एक विनम्र निवेदन करना चाहता हूं कि जब महंगाई की बात चलती है तो महंगाई दो टुकड़ों में बांटी जा सकती है। एक वह महंगाई जो किन्हीं कारणों से बढ़ जाए और दूसरी वह महंगाई जो सरकार बढ़ा दे। आज देश तबाह और बरबाद हो रहा है, जो महंगाई सरकार बढ़ा रही है। इसका आपके पास क्या जवाब है कि आपने आते ही 16 प्रतिशत रेल भाड़ा बढ़ाया? आपके मन में संसद के प्रति जरा भी सम्मान नहीं, आप 10-15 दिन इंतजार नहीं कर सकते थे? कल रेल बजट आएगा। आप संसद की अवमानना और अवहेलना ही नहीं कर रहे हैं, आप आपने आपको अधिनायकवाद की तरफ, डिक्टेटरशिप की तरफ ले जा रहे हैं, और आपने पार्लियामेंट चलने से पहले यह घोषणा कर दी कि हम पार्लियामेंट की परवाह नहीं करते। वह आप यहां भी कर सकते थे, 10 दिन में कितना फर्क पड़ गया? अगर यह महंगाई बढ़ी है, तो यह आपकी बढ़ाई हुई है। आपने 6 परसेंट माल भाड़ा बढ़ाया। अगर 6 परसेंट माल भाड़ा बढ़ा है, तो जो सामान जाएगा, वह बाजार में महंगा बिकेगा या नहीं बिकेगा? अगर वह बिकेगा, तो निश्चित रूप से महंगाई बढ़ेगी और इसकी जिम्मेदारी सरकार की होगी। आपने डीजल का दाम बढ़ाया। जब रेलवे स्टेशन से गोडाउन तक माल जाएगा और उसके बाद वहां से छोटे-छोटे शहरों और छोटे-छोटे कस्बो में माल जाएगा, तो वहां भी तो वह ट्रक या छोटे साधनों से जाएगा, वह दाम भी तो आपने बढ़ा दिया, तो महंगाई तो आपकी बढ़ाई हुई है। आपने महंगाई किसकी बढ़ाई? आपने महंगाई डिजल, पेट्रोल और पेट्रोलियम प्रॉडक्ट्स की बढ़ाई। आप गृहिणियों के चौके तक पहुंच गए और आपने सिलेंडर के दाम 16 रुपये बढ़ा दिए।

मान्यवर, सारी महंगाई तो आपकी बढ़ाई हुई है। आप कहते हैं कि यह जो महंगाई बढ़ी है, इस पर हम लगाम लगाएंगे। क्या आपको मालूम है कि आजकल उत्तर प्रदेश के बाजारों में क्या कहावत है? जब से आपकी केन्द्र की सरकार बनी है, जो जमाखोर हैं, मुनाफाखोर हैं, वे कह रहे हैं- "जब सैंया भए कोतवाल तो अब डर काहे का।" अब तो हमारी सरकार बन गई और यह सरकार तो हमने बनवाई। माफ कीजिएगा, आप गरीब जनता की पसंद नहीं थे, इस देश के चुनिंदा उद्योगपतियों ने आपको उम्मीदवार बनाया और उन्होंने आपको इस देश के इतिहास का सबसे महंगा चुनाव लड़वाया। इससे महंगा कोई चुनाव नहीं हुआ। अगर उन्होंने महंगा चुनाव लड़वाया है, तो इसलिए तो नहीं लड़वाया कि आपकी सूरत-शक्ल बहुत अच्छी थी या आपका पुराना इतिहास बहुत अच्छा था। आपको उन्होंने इसलिए महंगा चुनाव लड़वाया कि उन्होंने जितना लगाया है, उसका सौ गुना वसूलना है। महाभारत

कोई और पढ़े न पढ़े, जेटली जी ने पढ़ा होगा। माफ कीजिएगा, आपकी सरकार की हालत महाभारत के धृतराष्ट्र की तरह हो गई है। आपने आंखों पर पट्टी बांध ली है और जनता लुट रही है, जनता बिक रही है। बाजार में जा रही है, पिट रही है और आप इसलिए पट्टी बांधे हो कि चुनाव का जो खर्चा हुआ है, कुछ निकल जाए। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि आप बताएं इसको कैसे रोकेंगे। अभी हमारे एक दोस्त मुख्तार भाई बोल रहे थे, उनके दिल का दर्द मैं समझता हूं। बेचारे इतने वरिष्ठ को अब भी मंत्री नहीं बनाया। मैं नहीं जानता क्यों नहीं बनाया। वे कह रहे थे सरकार का इकबाल है। कैसा इकबाल है भाई। आप एक तरफ कहते हो, हमारे पासवान जी कहते हैं कि अफवाह उड़ायी जा रही है, हालात पैदा किए जा रहे हैं, इसलिए महंगाई बढ़ रही है। सो पासवान जी, बगल में घूमकर देखिए न, यह अफवाहबाज कौन है। यह अफवाहबाज तो आपके कृषि मंत्री हैं। इन्हीं ने कह दिया कि सूखा पड़ने वाला है। अब अफवाह अगर वे फैला रहे हैं, तो संकट तो पूरे देश में आप पैदा कर रहे हैं। तो अफवाह अगर किसी ने दी है तो आपके खुद मंत्रिमंडल के सहयोगी ने दी है, और अगर किसी की बात का सबसे ज्यादा यकीन है इस सरकार में तो जेटली साहब का। जेटली साहब का इकबाल है। इन्होंने कह दिया कि अक्तूबर और नवम्बर तक ऐसे ही दाम बढ़ते रहें। तो अब अक्तूबर और नवम्बर तक तो रुकने वाले नहीं, जब जेटली साहब ने कह दिया, हिन्दुस्तान के वित्त मंत्री ने कह दिया तो कैसे रुकेंगे? सच्चाई यह है कि यह जो दाम बढ़ रहे हैं, महंगाई बढ़ रही है यह किसान की वजह से नहीं बढ़ रही है, छोटे ईमानदार व्यापारियों की वजह से भी नहीं बढ़ रही है, यह बढ़ रही है जमाखोरों, मुनाफाखोरों की वजह से और उन लोगों की वजह से जिन्होंने तीन महीने, चार महीने अगर पैरोडी देखनी होती थी तब भी टेलीविजन पर आप ही दिखाई पड़ते थे, कॉमेडी देखनी होती तो आप ही दिखाई पड़ते थे और ट्रेजेडी जो देखनी होती थी अब देश की जनता देख रही है। तो कुल मिलाकर यह सब कुछ आपका किया धरा है। मुख्तार भाई इकबाल की बात कर रहे थे, तो इकबाल तो राजस्थान से शुरू हुआ है। बलात्कार होता है लेकिन आप में हिम्मत नहीं कि आप सरकार को हिलाएं-डुलाएं। बलात्कार के बाद भी आप मंत्री हटा नहीं सकते। अगर आप इकबाल की बात करते हो तो आपका इकबाल तो इतना बुलन्द है कि **...(व्यवधान)...**

एक सम्मानित सदस्य : महंगाई पर बात कीजिए। **...(व्यवधान)...**

श्री प्रमोद तिवारी : मैं समझ नहीं पाया कि ऐसा किसने कहा, अगर वे खड़े होकर बोल देते तो मैं उनका जवाब दे देता। महंगाई इसीलिए बढ़ी है कि आपके आने से लोगों को यह लग गया कि कानून-व्यवस्था नाम की चीज नहीं है, वरना आप मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए। गैर-कांग्रेसी सरकारें या गैर-भाजपाई सरकारों की बात छोड़िए, आप अपनी भाजपा सरकार की बात कर लीजिए। आपने कितने जमाखोरों के यहां छापे मारे, कितनों को जेल भेजा और आपसे बड़ा संविधान विशेषज्ञ कौन है जेटली जी, इस कानून से आप किसको गिरफ्तार करोगे? क्या यह कानून कोर्ट की स्क्रूटनी में एक दिन भी रुकेगा? यह जो 16 परसेंट रेल किराया आपने बढ़ाया, आप कह सकते हो कि पहले का निर्णय था। तो हमारी राजनीतिक इच्छा शक्ति के रहते बढ़ने नहीं दिया और आप इतने कमजोर इकबाल के निकले कि आते ही आपने घुटने टेक दिए, आपने उसे बढ़ने दिया। इसकी जिम्मेदारी आपकी है। मैं आपसे इतना जरूर कहना चाहूंगा।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Now, please conclude.

श्री प्रमोद तिवारी : अभी तो मैंने शुरू किया है। मान्यवर, मैं आपसे एक चीज जरूर कहना चाहता हूं, एक हालात होते हैं। **...(व्यवधान)...**

MR. DEPUTY CHAIRMAN: The Chairman has already set five minutes per speaker. So, please finish it now.

श्री प्रमोद तिवारी : उन्होने तो यही कहा है कि दो-तीन मिनट चल जाएगा।

मैं आपसे विनम्रतापूर्वक आग्रह करना चाहता हूं। यह जो महंगाई का मुद्दा है, यह इस देश की गरीब जनता के साथ जुड़ा हुआ है। आपने कहा, अच्छे दिन आएंगे। आए अच्छे दिन, लेकिन अगर जरा गौर से देख लें कि अच्छे दिन किस के आए? अच्छे दिन उनके आए जो इस देश को लूटते रहे हैं, अच्छे दिन उनके आए जिन्होंने इस देश के बाजार में हमेशा महंगाई बढ़ाई। अच्छे दिन उनके आए, पैसा देना ही पड़ा सरकार से साढ़े चार हजार करोड़। तो आपको भारत का किसान याद नहीं आया, भारत के पूंजीपति याद आए, गन्ने के मिल मालिक याद आए। लेकिन आपने यह गारंटी नहीं ली कि इस पैसे को आप सरकारों से बंटवा देते, कम-से-कम गन्ना किसानों तक वहां पहुंच तो जाता, जो पैसा दिया जा रहा है। बात करके देखिए, कहां जा रहा है? आप प्रदेश सरकारों को कोयला नहीं दे रहे हैं। आपके एक्सपर्ट लोग कर क्या कर रहे हैं? मुरादाबाद में दंगा कराना चाहते हैं, उत्तर प्रदेश में आग लगाना चाहते हैं। आपका जो गुजरात का फॉर्मूला है, मुजफ्फरनगर में उसका फायदा आपने उठाया। अब आप मुरादाबाद में करना चाहते हो। मैं सिर्फ आपसे कहना चाहता हूं कि यह दंगे-फसाद जितने आप कराओगे उससे महंगाई बढ़ेगी, बाजार में अस्थिरता आएगी, इससे काम चलने वाला नहीं है। मैं आप से सिर्फ एक बात कहकर अपनी बात खत्म करूंगा। महोदय, आज जो महंगाई बढ़ी है, इसके लिए अगर कोई जिम्मेदार है, तो हमारे सामने बैठी यह सरकार जिम्मेदार है, इस सरकार में बैठे लोग जिम्मेदार हैं क्योंकि इन्होंने चुनाव उनके पैसे से लड़ा है, जिसे अब ये उसे ब्याज सहित अदा करना चाहते हैं। महोदय, मेरा तो सीधा आरोप है कि अगर इस महंगाई की मार में देश की जनता है, तो उसकी जिम्मेदार भारत सरकार है। यह महंगाई बढ़ा रही है, अपने सारे संसाधनों से बढ़ा रही है और जब इसे रोकने की बात आती है, तो यह आंखों में पट्टी बांधकर इसलिए बैठ जाती है क्योंकि नजरें मिलाने की इसकी हिम्मत नहीं है। मान्यवर, आपने मुझे बोलने का समय दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री विजय गोयल (राजस्थान) : उपसभापति जी, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने महंगाई जैसे गंभीर मुद्दे पर मुझे बोलने का अवसर दिया।

महोदय, मैं पहले भी लोक सभा का मेंबर रहा हूं। मैंने पहले कभी ऐसा नहीं देखा कि अपोजीशन की तरफ से डिमांड हो और उसी समय वित्त मंत्री जी खड़े होकर कहें कि आप महंगाई पर चर्चा करा लीजिए। यह उन्होंने इसलिए कहा क्योंकि हमारा दामन साफ है, हमारे पास कहने को बहुत कुछ है। अभी तिवारी जी ने बड़े आराम से यह बात कह दी कि हमने उनके पैसे से चुनाव लड़ लिया। अगर महंगाई को आप इसका कारण बता रहे हैं, तो क्या आप 10 सालों से उन के पैसों से चुनाव लड़ रहे थे? हम सब जानते हैं कि महंगाई बढ़ी है, किन्तु अच्छे दिन इस बात के हैं कि सरकार तुरंत एक्शन ले रही है, अच्छे दिन इस बात के हैं कि प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी 24x7 काम कर रहे हैं। आज दोनों सरकारों में सब से बड़ा फर्क यह है कि आपके समय में जब प्याज की कीमत 80 से 100 रुपए किलो हो जाती थी, तब आप हरकत में आते थे, लेकिन आज जब जरा से भी दाम बढ़ते हैं तो यह सरकार तुरंत हरकत में आती है। अच्छे दिन इसलिए हैं कि लोग इस बात का विश्वास कर रहे हैं कि यह वह सरकार है जो गवर्नेंस करना जानती है। आपने 10 साल शासन किया और आप हमें 10 हफ्ते देने के लिए तैयार नहीं हैं। मुझे यह अच्छा नहीं लगता कि मैं खुद अपनी सरकार की प्रशंसा करूं कि उसने क्या-क्या स्टैप्स उठाए हैं। अच्छा होता, आप लोगों ने समाचार-पत्रों में पढ़ा होता या टी.वी. चैनल्स पर इस बात को देखा होता

3.00 P.M.

कि सरकार ने क्या-क्या स्टैप्स उठाए हैं। महोदय, सरकार ने एक-एक करके स्टैप्स उठाए हैं और अगर ये स्टैप्स पिछले 10 सालों में उठाए गए होते तो मैं समझता हूं कि आज हमें इस महंगाई का सामना ही नहीं करना पड़ता।

महोदय, हमारा देश दुनिया में सबसे ज्यादा साग-सब्जी पैदा करता है, किन्तु पिछले 10 सालों में 350 प्रतिशत तक इन के दाम बढ़े हैं। वर्ष 2004 से 2013 तक आप ने फूड कमोडिटीज के दाम 157 परसेंट तक बढ़ा दिए थे। आपने 2004 से प्याज के दाम 521 परसेंट बढ़ा दिए, चावल के दाम 137 परसेंट और गेहूं के दाम 117 परसेंट बढ़ा दिए। उपसभापति जी, मेरी सरकार ने सब से अच्छा काम यह किया कि तुरंत बैठकें की। ...**(व्यवधान)**...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Shri Shantaram Naik, please take your seat. ...*(Interruptions)*... Please don't disturb. ...*(Interruptions)*...

श्री विजय गोयल : महोदय, मेरी सरकार ने यह अच्छा काम किया कि तुरंत वित्त मंत्री जी ने बैठक की, तुरंत खाद्य मंत्री जी ने बैठक की और तुरंत प्रधान मंत्री जी ने बैठक की ...**(व्यवधान)**... मैं आपको नतीजे भी बताता हूं।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Mr. Goel, please address the Chair. ...*(Interruptions)*... Please address the Chair.

श्री विजय गोयल : ये नतीजे हैं, जिन से हमने प्राइस राइज को कंट्रोल किया है। मेरी सरकर ने तुरंत वित्त, खाद्य, वाणिज्य मंत्रालयों की बैठकें कीं और राज्यों के खाद्य मंत्रियों की बैठक बुलाकर इस बात को सुनिश्चित किया कि ये प्राइसेस और आगे न बढ़े। हमने इस बात का प्रयास किया कि हम प्याज के निर्यात के दामों को कंट्रोल करें। हमने एक्सपोर्ट का प्राइस 130 से 300 डॉलर्स प्रति मीट्रिक टन और 500 डॉलर्स प्रति मीट्रिक टन तक किया। यह हमारा प्रमुख कदम था, नहीं तो पहले इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट की तरफ ध्यान ही नहीं दिया जाता था। महोदय, ये पहले तब एक्शन में आते थे जब प्याज 70 से 80 रुपए तक बिकता था। हम चाहते हैं कि फार्म्स प्रोड्यूस में इम्प्रूवमेंट आए, हम चाहते हैं कि ब्लैक मार्केटिंग कम हो। महोदय, इनके समय में तो हम ने जमाखोरों पर छापे पड़ते हुए कभी भी नहीं सुना। उपसभापति जी, अभी यहां बिचौलियों की बात की जा रही थी, तो सारे बिचौलिए खराब नहीं हैं। यह देश का सिस्टम है, इसके अंदर बिचौलिए हैं, मिडिल मेंस हैं।

उनके भी लाभ और हानि हो सकते हैं। खराब वे हैं, जो ब्लैक-मार्केटिंग कर रहे हैं। मेरी सरकार ने ओनियन एक्सपोर्ट के साथ आलू के दामों को भी कंट्रोल किया है, उसकी एम.ई.पी. प्राइस तय की है। मेरी सरकार ने यह भी किया कि राज्य सरकारों को इस बात की अनुमति होगी कि कुछ चीजों की शॉर्टेज होने पर वे उनका आयात सीधे कर सकती हैं। मेरी सरकार ने ए.पी.एम.सी. एक्ट से उन सब चीजों को, जो खाद्य चीजें थीं, मुक्त किया था कि किसान आए और अपनी मर्जी से जिसको चाहे अपना माल बेच सकते थे, हमारी सरकार ने जगह-जगह गवर्नमेंट आउटलेट्स खोले और व्हीकल के थ्रु माल बेचने की शुरूआत की।

उपसभापति महोदय, अभी दस हफ्ते भी नहीं हुए, आप लोग हमें समय भी नहीं देना चाहते, जबकि जनता हमें समय देने के लिए तैयार है। जनता चाहती है कि यह जो सरकार आई है, कम से कम इसे एक साल तो देखें। नरेन्द्र मोदी जी, प्रधान मंत्री जी ने कभी भी यह बात नहीं कही कि मैं सौ

[श्री विजय गोयल]

दिन के अंदर महंगाई कम कर दूंगा, जैसा मनमोहन सिंह जी ने दावा किया था। उन्होंने कहा कि हम साठ महीने के लिए चुन कर आए हैं, हमारी सरकार को आप रिजल्ट देने दीजिए और उसके बाद परिणाम देखिए। आप में से कोई भी तारीफ नहीं कर रहा है। इतनी छोटी अवधि के अंदर इस सरकार ने कितने कदम उठाए हैं, अभी हमारी सरकार ने राज्यों को 50 लाख टन चावल और दिया, ताकि उसके दाम न बढ़ें। पल्सेज और एडिबल ऑयल का इम्पोर्ट स्टेट्स की सरकारें डायरेक्ट कर सकती हैं, 22 कमोडिटीज पर हम नजर रखे हुए हैं और आप पर भी नजर रखे हुए हैं, क्योंकि हम कार को चला रहे हैं और आप कार को रोक रहे हैं। मुझे एक वाकया याद आता है कि एक आदमी की कार खराब हो गई, वह इंजन खोल कर अपनी कार ठीक करने लगा और पीछे वाला जो आदमी था वह जोर-जोर से हॉर्न बजाने लगा। तो वह आदमी पीछे गया और उसने उससे कहा कि ऐसा कर, तू मेरी कार ठीक कर, मैं तेरा हॉर्न बजाता हूं, क्योंकि लगता है दोनों चीजें आपकी जरूरत हैं। आप क्या कर रहे हैं? आप बाधाएं उत्पन्न कर रहे हैं। मैं नहीं कहता कि अपॉजीशन को बोलने का हक नहीं है, किन्तु अपॉजीशन को बोलने का हक तब है, जब वह सरकार को कुछ मौका दे दे।

उपसभापति जी, कुछ बातें तिवारी जी ने बिल्कुल सही कही थीं। कुछ चीजें हमारे कंट्रोल में नहीं हैं, जैसे रेलवे के अंदर 25 हजार करोड़ रुपए का घाटा था। आप वाह-वाही लूटते रहे, आपने 60 हजार किसानों के कर्जे माफ कर दिए, वाह-वाही लूट ली, मगर किसानों के कर्जे माफ हुए या नहीं हुए, उन तक पैसा गया या नहीं गया, हमें मालूम नहीं है। आज मेरी सरकार भी चाहती तो वाह-वाही लूट सकती थी और रेलवे के किराए बढ़ाने के बजाय किराए कम कर सकती थी, किन्तु अच्छे दिन तभी आएंगे, जब सरकार कुछ सख्त कदम उठाएगी। मेरी सरकार सख्त कदम उठाने में विश्वास रखती है, क्योंकि अगर अभी आप थोड़ा कष्ट सहेंगे, तो आगे आने वाले समय में यह सरकार आपको राहत देने वाली है।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Okay. Please conclude now.

श्री विजय गोयल : उपसभापति जी, मैं इसलिए कहना चाहता हूं, क्योंकि किसी ने कहा है-

"हमारे सिर पर कांटों का ताज पहना कर
हमीं से देखिए कैसे गुलाब मांगते हैं।"

आपने दस साल के अंदर जो किया है, मैं उसकी निंदा नहीं कर रहा हूं। मैं इतना ही कह रहा हूं कि हर प्रधान मंत्री ने कोशिश की होगी। मनमोहन सिंह जी बहुत अच्छे प्रधान मंत्री रहे, अर्थशास्त्री रहे, सब कुछ रहा, उन्होंने अपनी पूरी कोशिश की होगी, किन्तु देश रसातल के अंदर चला गया था। अब यह सरकार आई है, इसको मौका दीजिए, यह काम करके दिखाएगी और अभी तक इसने जितने उपाय किए हैं, उतने उपाय इतने शॉर्ट टर्म के अंदर दूसरा कोई प्रधान मंत्री और दूसरी कोई सरकार नहीं कर सकती। यह मैं आपको कहना चाहता हूं। धन्यवाद।

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री रामविलास पासवान) : उपसभापति जी, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, हमारे साथी फाइनेन्स मिनिस्टर साहब विस्तार से जवाब देंगे। मैं सिर्फ एकाध चीजों के बारे में सदन का ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा। अभी हमारे साथी के.सी. त्यागी जी ने और काफी साथियों ने हम पर आरोप लगाया कि हम किसान-विरोधी हैं।

श्री के.सी. त्यागी : आगाह किया, आरोप नहीं लगाया।

श्री रामविलास पासवान : चलो, ठीक है। सर, मैं 1969 में एम.एल.ए. बना था, मेरा राजनीतिक जीवन 45 साल का है। हम लोग मर जाना पसंद करेंगे, लेकिन कभी भी किसान या गरीब या शेड्यूल्ड

कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्ज, बैकवर्ड, माइनॉरिटी कम्युनिटीज के अहित में अगर कोई काम होता है, तो हम उसे कभी बर्दाश्त नहीं कर सकते। कुछेक चीजें हैं, जो आप भी रहेंगे, हम भी रहेंगे, कोई भी रहेंगे, करेंगे। आपने किसान की बात कही, आप जानते हैं कि किसानों का साढ़े 13 हजार करोड़ रुपया मिल-मालिकों के यहां बकाया है, जो मिल-मालिक देने को तैयार नहीं हैं और वे दे भी नहीं सकते हैं। मिल बंद हो जाए, लेकिन वे देने के लिए तैयार नहीं हैं। खासकर के जहां गन्ने का उत्पादन होता है, जो हमारे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के साथी हैं, या हमारे महाराष्ट्र के साथी हैं, उनको यह सब मालूम है। उनको यह बात मालूम है। जो बात आपने कही कि एफ.आर.पी. हमारी नहीं है, तो एफ.आर.पी. प्राइस तय करती है, 210 रुपए हों या 218 रुपए हों, वह तय करती है। लेकिन यह भी सही है कि बिहार की सरकार ने कहा कि 210 के बदले में हम 265 देंगे। उत्तर प्रदेश की सरकार ने कहा कि मिल-मालिक 280 देगा। अब उसमें मिल-मालिक कहते हैं कि हम नहीं देंगे। किसान कहता है कि हमें लेना है, नतीजा यह हो रहा है कि चीनी मिलें बंद होने के कगार पर हैं। अब दो ही चीजें हैं कि चीनी मिलों को बंद कर दिया जाए और किसान को भूखा मरने दिया जाए। क्योंकि हर साल होता है कि दो साल के बाद, तीन साल के बाद जब पैदावार ज्यादा होती है, तो दाम कम हो जाता है। जब दाम कम हो जाता है, तो कभी कहते हैं कि लकड़ी गन्ने से ज्यादा महंगी हो गई और फिर किसान बोना बंद कर देता है और उसके दाम बढ़ जाते हैं। तो यह साइकिल बनी हुई है। इस परिस्थिति में... हम तो धन्यवाद देना चाहते हैं। हम कहां कहते हैं... हमारी सरकार को बने हुए तो 41 दिन हुए हैं। हम कहां कह रहे हैं कि हमारी सरकार ने उपज को बढ़ाया है, लेकिन यह बात सही है कि आप ही की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, उपज बढ़ी, गन्ने का प्रोडक्शन बढ़ा। इसमें दो मत नहीं हैं। चीनी का उत्पादन 2012-13 में 237 लाख टन था और उतना ही आज भी है, बल्कि उससे बढ़ा ही है या प्याज की जो कीमत थी, जो बात अभी हमारे साथी गोयल जी कह रहे थे, हम क्यों सख्त कार्रवाई करने की सोच रहे हैं? 2012-13 में हम नहीं थे, उस समय प्याज की कीमत क्या थी? तब के एग्रीकल्चर मिनिस्टर श्री शरद पवार जी यहां बैठे हुए हैं। तो 2013-14 में यह 168 लाख टन था, जो आज 2013-14 में बढ़कर 193 लाख टन हो गया है। इसी तरह आलू का उत्पादन 453 लाख टन था, जो 2013-14 में बढ़कर 464 लाख टन हो गया। गेहूं का उत्पादन 935 लाख टन था, वह बढ़कर 960 लाख टन हो गया। उसी तरीके से चावल का उत्पादन 10,052 लाख टन था, वह बढ़कर 10,062 लाख टन हो गया, तो हम यह कहां कह रहे हैं? पैदावार बढ़ी। लेकिन यदि आलू की पैदावार बढ़ी है, चीनी की पैदावार बढ़ी है, प्याज की पैदावार बढ़ी है, तो फिर ये दाम क्यों बढ़ रहे हैं? मामला यहां जाकर लटकता है और उसके लिए कहीं न कहीं, जिसको आप बिचौलिया कहिए, जिसके लिए अभी हमारे भाई गोयल जी ने कहा "जमाखोर", ये उसके लिए जिम्मेदार हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और मैं समझता हूं कि पूरे के पूरे सदन को हमने कहा कि यह राष्ट्रद्रोह का काम है। एक मंत्री की हैसियत से कहा, सोच-समझ कर कहा। ऐसे लोग जो समय का फायदा उठाकर देश की जनता को भूखे मारने की कोशिश करते हैं, उसको ज्यादा से ज्यादा कीमत पर बेचने की कोशिश करते हैं, वैसे लोगों को जो भी सजा दी जाए, कम है और ऐसे लोग जमाखोर, मुनाफाखोर ही नहीं हैं, बल्कि वे राष्ट्रद्रोह का काम भी करते हैं।

अब आपने कहा हमारे ऊपर चार्ज है गन्ना किसानों का। अब भला बताइए कि साढ़े तेरह हजार करोड़ रुपया गन्ना किसानों का है और मिल-मालिक कहते हैं कि हम नहीं देंगे। उसमें मेनका गांधी जी थीं, कलराज मिश्र जी थे, गडकरी साहब थे और श्रीमती सीतारमण भी थीं। हम सब लोग बैठे, बैठने के बाद कहा गया कि गन्ना किसान गांव में गन्ना नहीं दे रहा है, इसलिए आप लोग कोई रास्ता निकालो। हम लोगों ने तीन-चार रास्ते निकाले। एक रास्ता हमने यह निकाला कि जो एक्सपोर्ट इंसेंटिव था, जो

[श्री रामविलास पासवान]

एक साल के लिए बढ़ाया गया था, हमने कहा कि 3330 रुपए प्रति क्विंटल दो महीने के लिए बढ़ाया जाएगा। जो इम्पोर्ट ड्यूटी थी, उसे 15 परसेंट से बढ़ाकर 40 परसेंट कर दिया। जो ब्याज मुक्त लोन था, उसको तीन वर्ष से बढ़ाकर पांच वर्ष किया गया। जो एथनॉल है, उसका दाम कम होता है और चीनी का दाम ज्यादा होता है। अभी हमारे यहां दो परसेंट एथनॉल भी नहीं होता है और ब्राजील में चले जाएं तो 80 परसेंट, 85 परसेंट भी लाया जाता है। हम अपने पेट्रोलियम मिनिस्टर को धन्यवाद देना चाहते हैं, उन्होंने एग्री किया कि इसको हम 10 परसेंट तक ले जाएंगे और जो सबसे बड़ी बात थी, जो आपने कहा मिल-मालिकों के बारे में, अभी तक हमने किसी का नोटिफिकेशन नहीं किया है। हमने मिल-मालिकों को साफ तौर से कह दिया है कि यदि ये सारी चीजें तुम मानोगे और तुम कहो कि हम किसान का बकाया देंगे और... उसके बाद आपको मालूम है कि जो ब्याज मुक्त लोन था, उसमें जरूर दोनों को फायदा होगा, लेकिन हमने कहा है कि जब तुम आकर हमें बताओगे कि हम तुमको देंगे, किसान का पेमेंट करेंगे, तभी हम यह चीज लागू करेंगे, नहीं तो हम लागू करने वाले नहीं हैं। इसलिए मैंने कहा कि सदन को यह सोचना है कि किसान जिंदा रहे या मर जाए - यह सदन को सोचना है। यदि सदन को सोचना है तो यह जो साढ़े तेरह हजार करोड़ रुपए हैं, यह कोई मामूली चीज नहीं है। दूसरा, आपने खाद्यान्न के संबंध में कहा। अभी हम लोगों ने जो फैसला लिया है, वह बहुत कठोर फैसला लिया है। 1999 से लेकर 2004 तक आलू और प्याज एसेंशियल कमॉडिटी के अंतर्गत था, 2004 में सरकार बनी और इन दोनों चीजों को उसके अंदर से निकाल दिया गया। अभी हमने राज्यों के खाद्य मंत्रियों की बैठक बुलाई - हम धन्यवाद देना चाहते हैं- हर पार्टी के खाद्य मंत्री उसमें थे और हमारे फाइनेंस मिनिस्टर उसमें मुख्य अतिथि के रूप में थे। सब लोगों ने इस बात को माना। हमने उनसे कहा कि कोई पार्टी पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए। पार्टी पॉलिटिक्स करने के लिए बहुत जगहें हैं। आप लोग बताइए कि क्या-क्या हो सकता है। उन सब लोगों ने तीन-चार चीजों पर अपनी राय व्यक्त की। उन्होंने कहा कि एक कॉमन नैशनल मार्किट हो। आज हमारे पास कॉमन नैशनल मार्किट है ही नहीं। आप बगल में, पंजाब में चले जाइए, दूसरे राज्यों में चले जाइए। वहां मंडी सिस्टम है और उस मंडी सिस्टम में किसान को यह अधिकार नहीं है कि वहां का किसान दिल्ली में आकर आलू-प्याज को बेच सके। उनको मंडी के थ्रू बेचना पड़ता है। मंडी में जाकर उनको आठ रुपए किलो दाम मिलता है और यहां आकर उनको 22 रुपए किलो खरीदना पड़ता है। यदि वह सिस्टम टूट जाए और एक कॉमन मार्किट हो जाए, तो उनको फायदा हो सकता है। हम लोगों ने डीलिस्टिंग बनायी, स्टोर लिमिट हम लोगों ने जारी की। जो किसान हैं, उनको हमने यह नहीं कहा कि आप मंडी में जाकर मत बेचो। आप मंडी में भी बेच सकते हो, लेकिन मंडी के अलावा यदि आपको लगता है कि दूसरी जगहों पर अच्छा दाम मिलेगा तो आप वहां पर भी जाकर बेच सकते हो। जो एसेंशियल कमॉडिटी ऐक्ट है, उसके संबंध में हम लोगों की एक राय हुई, वह अभी हम लोगों के विचाराधीन है इसलिए हम कोई घोषणा नहीं करना चाहते, लेकिन वहां जितने भी खाद्य मंत्री थे, उन सबने कहा कि यह जो एसेंशियल कमॉडिटी ऐक्ट है, इसको नॉन-बेलेबल बनाइए। सब लोगों की यह राय थी कि डिटेंशन की अवधि 6 महीने से बढ़ाकर एक साल कीजिए। सब लोगों की राय थी कि प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड बनाइए, जिससे विपदा के समय में सारी की सारी चीजें दुरूस्त हो सकें। हमारे पास स्टोरेज की उचित व्यवस्था नहीं है। आज हमारे पास एफ.सी.आई. है, 40 परसेंट स्टोरेज हम एफ.सी.आई. के माध्यम से करते हैं। उदारीकरण की नीति बहुत अच्छी है, लेकिन जब तक गवर्नमेंट का कंट्रोल नहीं रहेगा, अगर हमारे पास एफ.सी.आई. नहीं होता तो हो सकता था कि गेहूं और चावल का दाम बढ़ जाता। आज क्यों प्याज का दाम बढ़ रहा है, आज क्यों आलू का दाम बढ़ रहा है? वह इसलिए कि हमारे पास स्टोरेज कैपेसिटी नहीं है। अगर हम तीन महीने, चार महीने के लिए स्टोरेज कैपेसिटी को ठीक कर लें, फिर मार्किट में अगर कोई दाम बढ़ाने की कोशिश भी करेगा तो वह

नहीं कर पाएगा। जैसा मैंने कहा कि अगर उत्पादन अधिक होगा तो वह दाम कैसे बढ़ा पाएगा? इसलिए हमने एक फैसला लिया। हम लोगों ने तो कम ही जगह पर कहा लेकिन सब खाद्य मंत्रियों ने कहा कि कम से कम हर जिले में एक स्टोरेज बनना चाहिए जिससे विपदा के समय में, आपातकाल के समय में जरूरत को मीट किया जा सके। पी.डी.एस. सिस्टम को दुरुस्त करने का काम है, उस पर हम अलग से चर्चा करेंगे। पचास लाख टन एक्स्ट्रा चावल पी.डी.एस. के माध्यम से वितरित हो। उसको हमने पचास लाख टन दिया है। गेहूं हमारे पास पड़ा हुआ है। अगर जरूरत पड़ेगी तो हम गेहूं को भी निकालने का काम करेंगे। हमने प्याज का न्यूनतम निर्यात मूल्य बढ़ाकर 500 डॉलर प्रति टन कर दिया, आलू का न्यूनतम निर्यात मूल्य 450 डॉलर प्रति टन कर दिया, डीलिस्टिंग कर दी। यहां आपने कहा, क्या कार्यवाही की जा रही है? लेफ्टीनेंट गवर्नर्स आए हुए थे। हम लोगों ने उनसे पूछा। 700-800 लोगों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्यवाही करके, एफ.आई.आर. करके उनको बंद करने का काम किया गया। सर, जैसा मैंने कहा, आप हर दस साल का रिकॉर्ड देखिए। जून-जुलाई से लेकर अक्तूबर तक ऑफ सीजन रहता है। आलू और प्याज होता नहीं है, अक्टूबर-नवम्बर में आकर हो जाएगा। इस पीरियड में जो सबसे बड़ी गड़बड़ करता है, जो किसान और गरीब के साथ जुल्म करने का काम करता है, वह बिचौलिया है, जमाखोर है। इसलिए बिचौलिए और जमाखोर के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्यवाही करने पर सरकार विचार कर रही है। हम आपसे वायदा करना चाहते हैं, कि यदि आप सब लोगों का सहयोग रहा, तो जो बीच में हेरा फेरी होती है, वह बंद हो जाएगी। हम पूरे सदन से यह अपील करना चाहते है; आग्रह करना चाहते हैं कि सब लोग मिलकर महंगाई की समस्या का समाधान निकालें, हां हम लोग सरकार में हैं, अगर हमारे खिलाफ में कुछ है, तो आप बोलिए। हमारी सरकार को बने हुए 41 दिन हुए हैं, हमें किस चीज के लिए छिपाना है, हम किस चीज के लिए छिपाएंगे, जब हमें 41 महीने हो जाएं तब आप हमें दोष दे सकते हैं। अभी तो जुम्मा-जुम्मा आठ दिन हुए हैं, जो चीज है, वह आपकी दी हुई है, आपके द्वारा परोसा हुआ है इसलिए एक चीज जो जमाखोरी है, उसके खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिए। यही मैं सदन से आग्रह करना चाहता हूं। आपने मुझे इंटरवीन करने का समय दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री उपसभापति : धन्यवाद । Now, the last speaker, Shrimati Rajani Patil. ...*(Interruptions)*...

श्री के.सी. त्यागी : उपसभापति महोदय, मुझे माननीय मंत्री जी से एक स्पष्टीकरण पूछने की अनुमति दे दीजिए। ...**(व्यवधान)**...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: I have called the last speaker. ...*(Interruptions)*... नहीं, नहीं। ...**(व्यवधान)**... श्रीमती रजनी पाटिल। ...**(व्यवधान)**...

श्री के.सी. त्यागी : उपसभापति महोदय, मैं एक स्पष्टीकरण पूछना चाहता हूं, मैं कोई आरोप नहीं लगा रहा हूं। ...**(व्यवधान)**...

श्री उपसभापति : आरोप नहीं है। मैंने उनको बोलने के लिए बुला लिया है। ...**(व्यवधान)**...

श्री के.सी. त्यागी : उपसभापति महोदय, मेरा एक क्लेरिफिकेशन है। रामविलास जी, चीनी मिलें बंद हो गई हैं, किसानों का पेमेंट होगा या नहीं, यह मैं पूछना चाहता हूं। आपने 11000 करोड़ रुपये ब्याज-मुक्त दिया है और उन्होंने कह दिया है कि हम पेमेंट नहीं कर सकते। अब दो रास्ते हैं या तो चीनी मिलों का अधिग्रहण हो या जो किसानों का सुसाइड रेट है, वह और बढ़े। दूसरी बात यह है कि आपने ऐसा क्यों कहा, जब आपकी चीनी मिल मालिकों के साथ बातचीत हो रही थी, तो आपने राज्यों के लिए

[श्री के.सी. त्यागी]

क्यों प्रतिबंध लगाया कि राज्य सरकारें बोनस न दें। ऐसा कभी पिछले 40-45 साल में नहीं हुआ, उनकी भी किसान नीति के खिलाफ हम लोग रहते थे, लेकिन वे भी कभी ऐसा नहीं कहते थे। फिर, आपने तिलहन और दालों के दाम जब तय किए, एम.एस.पी. तय की, भारतीय जनता पार्टी के घोषणा-पत्र में लिखा है कि एम.एस.पी.+50 परसेंट। आपने तिलहन के लिए भी कह दिया कि राज्य सरकारें खबरदार कि बोनस न दें। सर, मेरे सवाल का जवाब माननीय मंत्री जी ने नहीं दिया है।

MR. DEPUTY CHAIRMAN : The reply is coming from the Finance Minister.

श्री रामविलास पासवान : उपसभापति महोदय, मैंने किसी मिल-मालिक से अभी तक बात नहीं की है। मैंने किसान के प्रतिनिधि से जरूर बात की है।

MR. DEPUTY CHAIRMAN : Now, Shrimati Rajani Patil. You can take only five minutes.

श्रीमती रजनी पाटिल (महाराष्ट्र) : सर, मैं आपको धन्यवाद देना चाहती हूं कि इस सदन में एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय, जो महिलाओं के लिए खासतौर पर उनके दिल का विषय है, उस पर आपने चर्चा करने का मौका दिया और उसमें हिस्सा लेने के लिए आपने मुझे यहां पर आमंत्रित किया है। मैं सभा के सभी सम्मानित सदस्यों की बात को बहुत गंभीरता से सुन रही थी। इसमें कोई शक नहीं है कि हर एक का मकसद एक ही है और हर एक को इस महंगाई से छुटकारा चाहिए। कुछ महीने पहले जब चुनाव हुए तो हमारे यहां सपनों के सौदागर आ गए, अपने सपने बेच दिए और हमारे देश की गरीब जनता उन सपनों को मुफ्त में लेते-लेते परेशान हो गई और अब उनको यह कहने की नौबत आ गई कि क्या से क्या हो गया, क्या किया था हमने, क्या आपसे अपेक्षा की थी और आपने क्या दिया है।

सर, अभी मैं श्री रामविलास पासवान जी की बात को बहुत गौर से सुन रही थी। मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगी कि जो उन्होंने आंकड़ेबाजी की, उस आंकड़ेबाजी में ही कांग्रेस पार्टी का यश सम्मिलित है, यह मैं कहना चाहूंगी। जिस तरह से उन्होंने हर चीज़ के बारे में आंकड़ेबाजी की है, इसमें बहुत बड़े पैमाने पर 10 सालों में बहुत तरक्की हुई है। उसमें ही मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी का जो यश है, कांग्रेस पार्टी की जो प्रगति है, उससे यह है कि बहुत अच्छी तरह से इस देश को आगे ले जाने का काम गत 10 सालों में हुआ है, उसके बारे में कोई भी शंका व्यक्त नहीं करेगा। लेकिन गए तीन हफ्तों के बीच में सपनों के सौदागर ने जो वायदे किए थे, जो चीज उन्होंने जनता से बोली थी, हम जब भी टी.वी. देखते थे, तो एक मध्यमवर्गीय महिला आती थी और बोलती थी कि महंगाई करने वालों जनता आपको माफ नहीं करेगी, यही शब्द हम सुनते आए हैं। दो महीने तक लगातार हम यही सुनते आए, चाहे कोई भी चैनल टी.वी. पर लगाओ, यह करने वालो जनता माफ नहीं करेगी, महंगाई करने वालो जनता माफ नहीं करेगी। अब मैं यह कहना चाहूंगी कि इस तरह से झूठे सपने दिखाकर, आपने जो महंगाई 15-20 दिनों में बढ़ाई है, इसके लिए आपको जनता माफ नहीं करेगी, यही मैं कहना चाहती हूं।

मैं एक महिला होने के नाते सदन को यह बताना चाहती हूं कि सभी को मालूम है कि यह सत्र डेढ़ महीने का है। मैं कल जैसे ही थैला लेकर बाजार में सब्जी लेने गई, तो मुझे पता चला कि जिन चीजों, सब्जियों और फ्रूट के लिए मेरे अकेली के लिए 500 रुपए लगते थे, उन चीजों के लिए मुझे एक हजार रुपए खर्च करने पड़े। यह सब देखकर मैं चौंक गई कि किस बेदर्दी से महंगाई बढ़ाई गई है। इसका उत्तर सत्ताधारी पक्ष के पास नहीं है।

सर, महिलाओं के लिए जो सबसे ज्यादा चुभने वाली बात है, वह है एल.पी.जी. गैस की कीमत। अभी दस दिन पहले ही नॉन सब्सिडाइज्ड गैस सिलेन्डर की कीमत 23.75 रुपए बढ़ाई गई है। जिन महिलाओं का संबंध किचन से है, उनको इससे बहुत फर्क पड़ता है। सर, आजकल रमजान के दिन चल रहे हैं। मैंने यह सुना है कि रमजान खोलने के लिए फ्रूट खाए जाते हैं। अगर आप बाजार में जाकर फ्रुट्स के दाम देखेंगे, तो पता चलेगा कि अगर कोई भी गरीब मुसलमान रमजान का इफ्तार करने के लिए फ्रूट खाने जाएगा तो इसके लिए उसकी जेब पर भारी असर पड़ेगा, मैं यहां पर यह बात कहना चाहती हूं। आप प्याज ले लीजिए, शक्कर ले लीजिए, धान ले लीजिए, दूध ले लीजिए या दाल ले लीजिए, इन सभी चीजों के लिए आकाश को छूने वाली महंगाई हो गई है, इसलिए इस महंगाई को काबू में लाने की बहुत आवश्यकता है। सर, मैं आपके माध्यम से कहना चाहती हूं कि यह सरकार महंगाई को रोकने में नाकामयाब हुई है और पूरी तरह से अन-सक्सेसफुल हो गई है। इन सब चीजों के दाम बढ़ाने से अगर किसानों को फायदा होता, तो हम समझ सकते थे। सर, दुख की बात यह है कि चीजों के दाम तो बढ़ गए हैं, लेकिन किसानों को कोई फायदा नहीं हुआ है। इससे तो बिचौलियों को ही फायदा हो रहा है, घूसखोरों को हो रहा है और जो जमा करने वाले लोग हैं, उनको फायदा हो रहा है। मैं किसानों के क्षेत्र से आती हूं और मुझे मालूम है, इससे न तो किसानों को फायदा मिल रहा है और न ही लोगों को मिल रहा है। अगर किसी को फायदा मिल रहा है, तो जो बिचौलिया लोग है,उनको मिल रहा है। मैं अभी इस बारे में यहां और चर्चा नहीं करना चाहती, क्योंकि मुझसे पहले बड़े-बड़े लोगों ने इस पर चर्चा की है।

सर, अभी जो डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़े हैं, इनके बढ़ने से सभी तरफ से महंगाई बढ़ गई है। सर, मैं आपके माध्यम से सबसे महत्वपूर्ण बात सदन में कहना चाहती हूं, जो मुझे सबसे बड़ी लगती है और वह यह है कि बजट से पहले जो रेलवे के दाम 14 प्रतिशत बढ़ाए गए हैं, इससे लोगों को बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। हमें इस ओर बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है।

सर, मैं आपके माध्यम से यही कहना चाहूंगी कि इस सरकार ने वायदे तो बहुत किए थे, लेकिन एक भी वायदा नहीं निभाया। अभी-अभी गोयल साहब ने बोला है कि हमें बहुत कम समय मिला है। गोयल साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं कि हम बहुत कम समय में आपके ऊपर टीका कर रहे हैं, लेकिन मराठी में एक कहावत है, चावल पका है या नहीं, यह देखने के लिए हर चावल के दाने को दबाकर देखने की जरूरत नहीं है। अगर हमें देखना है तो एक ही चावल के दाने को दबाकर देखेंगे, तो हमें पता चल जाएगा कि पूरे चावल तैयार हुए हैं या नहीं। इस तरह से हमें ऐसा लगता है ...**(व्यवधान)**... कि यह तो शुरूआत है। ...**(समय की घंटी)**... अगर शुरुआत इस तरह से हो रही है, तो उसका अंत भी इसी तरह से होने वाला है। मुझे नहीं लगता है कि यह सरकार महंगाई कम करने में कामयाब होगी। जिन महिलाओं ने इसको वोट दिया है और टी.वी. पर आकर कहा है ...**(व्यवधान)**...

श्री उपसभापति : ओ.के., ओ.के. धन्यवाद।

श्रीमती रजनी पाटिल : अपील की है कि महिला ही उनको घर में बैठाएगी। अभी इनको घर में बैठाने की आवश्यकता है, यही मैं आपके माध्यम से कहना चाहती हूं।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Now, the hon. Finance Minister will reply.

DR. K. KESHAVA RAO (Andhra Pradesh): Sir, I am not speaking about ...*(Interruptions)*... The irony is I represent the 8th largest Party in the Parliament.

[Dr. K. Keshava Rao]

Yet, I do not get time from the Chair either to speak on the President's Address or on this subject ...*(Interruptions)*.... Please, ...*(Interruptions)*... Will the Minister hear me? ...*(Interruptions)*....

MR. DEPUTY CHAIRMAN: You did not give your name.

DR. K. KESHAVA RAO: Sir, I want to submit one thing. Whenever the Adjournment Motion is taken up, what the Chair said was, automatically the Leader of the Opposition would speak first and the Members of other political parties would speak later. When I went up to the Secretary-General, he said, 'Your name is there'

MR. DEPUTY CHAIRMAN: What transacted between you and the Secretary-General cannot be spoken here. No, no; your name is not here, otherwise, I would have called you.

वित्त मंत्री, कॉरपोरेट कार्य मंत्री, रक्षा मंत्री (श्री अरुण जेटली): माननीय उपसभापति जी, एक गंभीर विषय के ऊपर आज नेता प्रतिपक्ष ने इस पर चर्चा का आरंभ किया है। एन.डी.ए. की यह सरकार क्योंकि एक संवेदनशील सरकार है, और बढ़ती हुई कीमतों को लेकर सारे देश की जो चिंता है, वह सबसे अधिक हमारी चिंता थी है, इसलिए हमें इस बात पर कोई संकोच नहीं था कि इस विषय के ऊपर तुरंत चर्चा होनी चाहिए। यह चर्चा केवल औपचारिकता का विषय नहीं है कि ससद का सत्र आरंभ हुआ है और हम पहले ही दिन चर्चा करें। बढ़ती हुई कीमतों और विशेष रूप से जिन तीन विषयों का जिक्र किया गया है, उनके कारणों में जाना और उनका हल ढूँढ़ने का प्रयास करना अति आवश्यक है। मुझे थोड़ा विचित्र इसलिए लगा, क्योंकि जो लोग दस वर्ष से शासन में थे और जिन्होंने देश की अर्थव्यवस्था को इस कगार पर लाकर खड़ा किया है, जिसकी वजह से पूरे देश में चिंता है, आज वही दूसरों के ऊपर दोष डालने का प्रयास कर रहे हैं। एन.डी.ए. की सरकार को तो कार्यकाल संभाले हुए अभी केवल पाँच सप्ताह हुए हैं, अभी छह सप्ताह भी पूरे नहीं हुए हैं, एक छोटे सत्र के बाद यह पहला सत्र है, जिसमें कल रेल बजट पर और बाद में आम बजट पर सरकार को अपनी नीतियाँ स्पष्ट करने का अवसर मिलेगा। अभी तक तो उन नीतियों की घोषणा भी नहीं हुई है, उसका भी पहला अवसर इस सत्र में है। लेकिन उससे पहले यह कह देना कि हिंदुस्तान की रेल के जो भाड़े बढ़ गए या आवश्यक वस्तुओं, खाद्यान्न पदार्थों की कुछ कीमतें बढ़ गईं या कुछ पेट्रोलियम प्रॉडक्ट्स डीजल की कीमतें बढ़ गईं और उसके लिए आप जिम्मेदार हो, इसका आधार क्या है? कुछ वस्तुओं की कीमतें बढ़ती हैं क्योंकि वे वस्तुएँ उपलब्ध नहीं होतीं। अब इन सबकी उपलब्धि की व्यवस्था करना, अर्थव्यवस्था का जो विद्यार्थी है, वह जानता है कि उसको पाँच सप्ताह में पूरा करना, संभव नहीं है, The concerns of the supply side should have been addressed in the last ten years. The storage capacities of cold chain should have increased in the last ten years. यह तो हुआ नहीं। अब हमारे मित्र प्रमोद तिवारी जी कह रहे थे कि रेल का विषय गंभीर है कि आपने आते ही चौदह परसेंट रेल कीमतें बढ़ा दीं। मेरे यूपीए के साथी यह एक बात समझ लीजिए आप किस स्थिति में रेल को छोड़कर गए हैं। आप इसको भी समझ लीजिए आप कि किस तरीके से देश का शासन नहीं चलना चाहिए। यूपीए सरकार के ऊपर इस बात का एक बहुत बड़ा आरोप लगता रहा है कि जहाँ कड़े निर्णय करने की आवश्यकता होती थी, वह उससे बचती रही और इस वजह से देश की यह परिस्थिति हुई। इस साल फरवरी महीने में आम बजट और रेल बजट इंटेरिम बजट्स के रूप में आए। फरवरी के महीने में जब यूपीए सरकार ने

भारतीय रेल की, जो रेल भारत की लाइफ लाइन है, अंग्रेज जब भारत छोड़कर गए थे तो उन्होंने हाईवेज नहीं बनाए थे, लेकिन उन्होंने रेल का एक नेटवर्क बनाया था, उस नेटवर्क को हमने सन् 1947 के बाद बहुत बड़ा किया हो, ऐसा नहीं है। यात्रियों का जो भाड़ा होता है, वह कम होता है, उससे घाटा होता है, जो फ्रेट होता है, उसमें से थोड़ा मुनाफा आता है और क्रॉस सब्सेडाइजेशन से रेल चलती है। सरकार चाहें किसी की भी रही हो यह रेल का पुराना सिद्धांत रहा है। फरवरी के महीने में जब इंटेरिम बजट आना था, तो भारतीय रेल की क्या स्थिति थी, इसके लिए मैं आपके सामने उस वक्त के सरकारी दस्तावेज की सिर्फ दो-तीन लाइनें पढ़कर बताना चाहता हूं। उस वक्त यह स्थिति थी कि यात्रियों के ऊपर जो भाड़ा लगता था, उसके आधार पर रेल का घाटा 30 हजार करोड़ रुपये बैठ रहा था। A sum of ₹ 30,000 crores was the loss on passenger front. For any public utility to run, the users must pay.

SHRI DEREK O'BRIEN: Sir, ...*(Interruptions)*...

SHRI ARUN JAITLEY: Sir, I am not yielding. ...*(Interruptions)*...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Mr. Derek, he is not yielding. ...*(Interruptions)*... No, please, he is not yielding. ...(Interruptions)... Mr. Derek, he is not yielding, please sit down.

SHRI DEREK O'BRIEN: Sir, just one minute. Whether it is ₹ 25,000 crores or ₹ 8,000 crores, the question here is, one of their sins has been added and compounded to their sins. So, we don't want an answer for their mistakes. Why are they implementing their mistakes? That is the question, Sir.

SHRI ARUN JAITLEY: Sir, I don't know if those who administered the Railways in the past were the original sinners. My friend from the Trinamool Congress goes into the question should realise where the shoe started pinching. ...*(Interruptions)*...

SHRI DEREK O'BRIEN: Sir, these numbers are disputable ones. ...*(Interruptions)*...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: He is not yielding, please sit down. ...*(Interruptions)*...

SHRI DEREK O'BRIEN: Sir, the logic is not right. Sir, we are walking out. They have cited the Executive Memo. ...*(Interruptions)*...

(At this stage some hon. Members left the Chamber)

SHRI ARUN JAITLEY: Sir, in February, 2014, the passenger loss of the Railways is ₹ 30,000 crores. This has to be subsidised by freight and the Railways is losing out on freight to road transport. इस परिस्थिति में रेलवेज़ क्या करती? रेलवेज़ की तरफ से प्रस्तावना आई कि रेल के भाड़े में वृद्धि की जाए, पैसेंजर फेयर को 10 परसेंट बढ़ा दिया जाए और फ्रेट को 5 परसेंट बढ़ा दिया जाए। रेलवेज़ का एक फार्मूला है कि जब भाड़ा बढ़ता है, तो जो फ्यूल की कीमत बढ़ती है, उसमें फ्यूल एडजस्टमेंट चार्ज जुड़ जाता है। इसलिए 10 परसेंट के साथ उसका फ्यूल

[Shri Arun Jaitley]

एडजस्टमेंट चार्ज जुड़ेगा और 5 परसेंट के साथ उसका फ्यूल एडजस्टमेंट चार्ज जुड़ेगा। चूंकि रेलवेज का घाटा बहुत बढ़ चुका था और अगर घाटा बढ़ता गया, तो रेल का चक्का जाम भी हो सकता है, इसलिए सुविधाओं में सुधार हो, उसके स्थान पर रेलवेज़ क्या करती? स्वाभाविक था कि उस वक्त वह कहती कि घाटा बढ़ा है, इसलिए इसका थोड़ा सा भाड़ा, 10 परसेंट, 5 परसेंट बढ़ाना पड़ेगा और उसमें फ्यूल एडजस्टमेंट चार्ज डालना पड़ेगा। रेलवे बोर्ड इन्टरिम बजट से पहले इस प्रस्तावना को लेकर 6 फरवरी को सरकार के सामने जाता है। 11 फरवरी को उस वक्त के प्रधान मंत्री जी इस बढ़ोतरी को स्वीकृति दे देते हैं और स्वीकृति देते वक्त कहते हैं, मैं केवल एक लाइन पढ़ दूँ --- "This was discussed by the hon. Minister of Railways with the hon. Prime Minister on 10tn February, 2014 when the undersigned was also present. At the hon. Prime' Minister's suggestion, it was decided to implement the fare and freight revision with effect from the first week of May, 2014." घाटा फरवरी में हो चुका है, रेल का चक्का जाम होने वाला है, पर चूँकि उस वक्त यह अंदाजा था **...(व्यवधान)...** उस वक्त यह अंदाजा था कि चुनाव मई में हो जाएगा, तो प्रस्तावना को यह मंजूरी दी कि भाड़ा बढ़ाओ, लेकिन चुनाव एक बार सिर से टल जाए, उसके बाद बढ़ाओ। चुनाव मई में हो गया। 16 मई को चुनाव के परिणाम आ रहे थे, इस आदेश के अनुसार रेलवे बोर्ड ने 16 तारीख की दोपहर को ये भाड़े बढ़ा दिए **...(व्यवधान)...**

SHRI MADHUSUDAN MISTRY: Sir, can the hon. Minister cite here the communication between the then Railway Minister and the then Prime Minister? ...*(Interruptions)*...

THE MINISTER OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (SHRIMATI SMRITI ZUBIN IRANI): Sir, the hon. Minister is not yielding. ...*(Interruptions)*...

एक माननीय सदस्य : सच देश के सामने आना चाहिए **...(व्यवधान)...**

SHRI T.K. RANGARAJAN (Tamil Nadu): You would have cancelled it. ...*(Interruptions)*...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please, please. ...*(Interruptions)*... Sit down, please. ...*(Interruptions)*... No, no; sit down.

SHRI MADHUSUDAN MISTRY: Then, all communications between the then Chief Minister of this country and the Prime Minister should also be ...*(Interruptions)*...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: You know it. Sit down. ...*(Interruptions)*...

SHRI T. K. RANGARAJAN: Sir, both the Opposition and the Treasury Benches are responsible for this. ...*(Interruptions)*...

श्री उपसभापति : बैठिए-बैठिए **...(व्यवधान)...** आप लोग बैठिए। **...(व्यवधान)...**

SHRI MADHUSUDAN MISTRY: Sir, they are trying to justify themselves because. ...*(Interruptions)*...

THE MINISTER OF URBAN DEVELOPMENT; THE MINISTER OF HOUSING AND URBAN POVERTY ALLEVIATION AND DEVELOPMENT; THE MINISTER OF

PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI M. VENKAIAH NAIDU): Mr. Deputy Chairman, Sir, the hon. Leader of the House is on his legs. He is not yielding. ...*(Interruptions)*...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Now, all of you are shouting. Sit down; sit down. ...*(Interruptions)*...

श्री एम. वेंकैया नायडू : यह क्या तरीका है? हम लोगों ने आपकी सारी बातें सुनी **...(व्यवधान)...**

श्री उपसभापति : मिस्त्री जी, बैठिए **...(व्यवधान)...** Mr. Mistry, take your seat.

श्री एम. वेंकैया नायडू : आप लोग इस बात से क्यों इंकार करते हैं? **...(व्यवधान)...**

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Mr. Mistry, please sit down. The Minister is not yielding. Unless you raise a point of order I cannot allow all this. Sit down. The Minister is not yielding.

SHRI ARUN JAITLEY: Sir, on the 16th of May, when the election results were being announced, half way through the results, the Railway Board issues a Notification giving effect to the then Prime Minister's directive. The fares are implemented. By the evening, the Minister knows that his Government is going; the results were clear. At 7 in the evening, having approved the tariffs in February itself, to be given effect in May, because the Railways are running in a loss, the outgoing Minister passes another Order saying, "What you have done in the afternoon should be rescinded, and this matter should be decided by the next Minister". ...*(Interruptions)*...

SHRIMATI VIPLOVE THAKUR (Himachal Pradesh): It was his right.

SHRI ARUN JAITLEY: Sir, I am ...*(Interruptions)*...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Sit down; sit down. ...*(Interruptions)*... Please sit down.

SHRI ARUN JAITLEY: Sir, when we are discussing price rise, and one of the issues is, why the railway fares are being raised, the House must know the full facts. The Railways were running in a loss. The UPA Government, in February, decided to raise this fare. ...*(Interruptions)*...

SHRI P. RAJEEVE (Kerala): You can explain all these things in the Railway Budget.

SHRI ARUN JAITLEY: Since you raised it today. ...*(Interruptions)*...

SHRI P. RAJEEVE: Why are you not waiting for that?

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Mr. Rajeeve, please sit down. ...*(Interruptions)*...

SHRI PRAKASH JAVADEKAR: You wanted the discussion today. ...*(Interruptions)*...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: No, no; don't interrupt. ...*(Interruptions)*...

SHRI P. RAJEEVE: The Prime Minister tweeted against the former Government. Why are you not waiting for the Railway Budget? ...*(Interruptions)*...

SHRI ARUN JAITLEY: Sir, all that I am saying is what the present Minister has done is, he was faced with a Hobson's choice. He allows the Railways to continue to bleed, and, then, hides behind some facts and says, "I won't raise the fare", and we reach a situation a few months down the road that the Railways is unable to operate. Does he follow the weak-kneed policies of his predecessors that unpopular decisions can't be taken even if they are in national interest? Does he then take these decisions and place these facts before the rest of the country that to run the railways this decision was necessary? ...*(Interruptions)*... तो इसलिए, मैं नेता प्रतिपक्ष से सिर्फ यह कहना चाहूँगा कि यह जो भाड़ा बढ़ा है, यह आपके खाते का है और हमारे खाते में यह बढ़ता है या नहीं बढ़ता है, यह आपको कल पता चलेगा। ...**(व्यवधान)**...

श्री मोहम्मद अली खान (आंध्र प्रदेश) : सर, ...**(व्यवधान)**... आप आने से पहले बता रहे थे कि ...**(व्यवधान)**...

†[جناب محمد علی خان : سر، ...(مداخلت)... آپ آنے سے پہلے بتا رہے تھے کہ ...(مداخلت)...]

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please sit down. ...*(Interruptions)*...

SHRI P. RAJEEVE: Is this a 'UPA-III' Government?

...*(Interruptions)*...

श्री अरुण जेटली : यह विरासत थी आपकी, जो आप छोड़ कर गए हैं। ...**(व्यवधान)**... यह विरासत थी आपकी, जो आप छोड़ कर गए हैं।

आपने कहा कि डीज़ल के दाम बढ गए। यू.पी.ए. सरकार ने तय किया था कि आज पेट्रोल मार्केट-लिंक्ड प्राइज के साथ जुड़ा हुआ है। पेट्रोल के दाम डीकंट्रोल्ड है। डीज़ल के संबंध में आपकी नीति थी कि हर महीने 50 पैसे इसका दाम बढ़ा दिया जाए। लेकिन, चुनाव के दो महीने में दाम नहीं बढ़ाया गया। इस नीति को कार्यान्वित करते हुए उन दो महीनों का जो बैकलॉग था, एक रुपया बढ़ा दिया गया,तो आज आपने कहा कि मैं स्थगन का प्रस्ताव देता हूँ। ...**(व्यवधान)**...

प्रो. राम गोपाल यादव : अगर आप इन्हीं की नीति अपनाएंगे तो अच्छे दिन कैसे आएँगे? ...**(व्यवधान)**...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: He is not yielding. .... *(Interruptions)*...

SHRI ARUN JAITLEY: Therefore, for two months because of election period and code of conduct it is not raised. Now, when that effect is given because the policy was to link it to the market. And, in any case if any of my friends looks at it, I would urge them,

†Transliteration in Urdu Script.

to kindly look at what the plight of crude oil price is — after the Iraq crisis the Brent crude has gone up to 115 dollar. The cost of the Indian basket has also increased. There are only two ways of funding that basket, either you marginally increase the diesel price or you increase the taxes, so that the Exchequer supplements those prices. Therefore, the entire increase, at least, my friends in the UPA and the Congress Party cannot say this because it was a culmination of their policy of a 50 paise increase every month and two months' increase had to be effected.

जहाँ तक खाद्य पदार्थों की कीमतों का सवाल है **...(व्यवधान)...** उपसभापति जी, जहाँ तक खाद्य पदार्थों की कीमतों का प्रश्न है, पिछले दो वर्षों से किन वस्तुओं की कीमतें बढ़ी हैं? दो वस्तुएँ, जिनका सबसे ज्यादा जिक्र होता है - प्याज और आलू। जुलाई से नवम्बर की अवधि, जब रबी की फसल आ चुकी होती है और प्रारंभिक खरीफ की फसल अभी बाजार में नहीं आई होती है, तो पिछले कई वर्षों से इस अवधि काल में कीमत बढ़ती थी। सरकार कीमत बढ़ने के बाद अपनी नींद से जागती थी और बाजार के अंदर सामानों को लाना और कीमतों को घटाना शुरू होता था, तो यह दिसम्बर के बाद घटनी शुरू हो जाती थी। पिछले कुछ वर्षों में कीमतें कहाँ तक पहुँची? जो कीमत 14, 15 और 16 रुपए होती थी, वह इस अवधि काल में 70, 80 और 100 रुपये तक गई। 70, 80 और 100 रुपये तक कीमतें पहुँच जाती थीं, पिछले कुछ वर्षों में यह प्रशासन था। जैसे ही इस बार कीमत 25 रुपये को छूने लगी तो इस सरकार ने केवल दिल्ली में ही नहीं बल्कि पूरे देश में कदम उठाने आरंभ कर दिए। इसने मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस फिक्स किया। पहले प्याज का मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस 300 डॉलर प्रति मीट्रिक टन फिक्स किया गया। 2 तारीख को उसको बढ़ा कर 500 डॉलर प्रति मीट्रिक टन कर दिया गया। आलू का 450 डॉलर प्रति मीट्रिक टन फिक्स किया गया। उसके बाद 3 तारीख को राज्यों को हिदायत दी गई की मिनिमम स्टॉक होल्डिंग मेंटेन कीजिए और जो भी कोई व्यापारी आवश्यक से ज्यादा अपनी स्टॉक होल्डिंग रखेगा, तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू कीजिए। कई स्थानों पर, दिल्ली जैसे स्थान पर सरकारी तंत्र के माध्यम से, सफल के माध्यम से तीन-चार नौ नए रिटेलिंग के काउंटर्स खोल दिए गए ताकि उस कीमत को 25 रुपए से बढ़ने न दिया जाए, जो 70 रुपए, 80 रुपए तक पिछले वर्षों में जाती रही है, उसका नियंत्रण आरंभ से शुरू किया। इस अवधि काल में कीमत बढ़ती हैं, लेकिन सरकार की क्षमता इसके आधार पर बनती है कि उसको नियंत्रित रखने में सरकार काबिल हो सकती है या नहीं हो सकती है। पासवान जी ने ठीक कहा कि पैदावार आलू की भी ज्यादा हुई है, प्याज़ की भी ज्यादा हुई है और इसलिए इनके दाम बढ़े, इसका कोई कारण नहीं था। दाम बढ़ने के पीछे जो कारण था कि जो मार्केट इंटरमीडिएट्रीज़ हैं, वे उसमें कोई रुकावट पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं और उनके खिलाफ कदम उठाए गए, जैसे सैंकड़ों की तादाद में सर्च होना, रेड होना, आदि। अब उनकी तरफ से शिकायतें शुरू हो गई हैं, लेकिन ये सारा कुछ करके आज भी कीमत जो 70 और 80 रुपए जाती थी **...(व्यवधान)...**

श्री नरेश अग्रवाल : सर, एक भी जगह कार्रवाई नहीं हुई है **...(व्यवधान)...** जमाखोर पर कार्रवाई नहीं हो रही है **...(व्यवधान)...**

श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी : सर, कहां रेडज़ हो रही हैं? **...(व्यवधान)...** गुजरात में हो रही हैं या रायपुर में हो रही हैं? **...(व्यवधान)...** कहां रेडज़ हो रही हैं? **...(व्यवधान)...**

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please let him speak. ...*(Interruptions)*...

श्री अरुण जेटली : उसको नियंत्रित रखा जाए। सरकार ने नियंत्रित रखा। मैं केवल अपने मित्रों से इतना कहूंगा कि इस अवधि में पिछले दो वर्षों में इन दोनों वस्तुओं की कीमत कहां तक पहुंची थी और इस बार जो कार्रवाई की गई, हर राज्य के खाद्य मंत्री को बुलाया गया, उनके साथ हमारे मंत्री की बैठक हुई और सर्वसम्मति से निर्णय हुआ कि क्या-क्या कार्रवाई करनी है। उत्तर प्रदेश के जो मंत्री आए, उन्होंने कहा कि आप इतना पैनिक क्यों कर रहे हैं, हमारे यहां तो इसकी कीमत 20 रुपए है। इसको नियंत्रण में रखा गया और सरकार इस बात के लिए वचनबद्ध है कि सरकार इसको नियंत्रित निश्चित रूप से रखेगी, क्योंकि इस विषय को हम लोग गंभीर मानते हैं, संवेदनशील मानते हैं और इसलिए इन वस्तुओं की कीमतें न बढ़ें, क्योंकि इनकी उपलब्धि बहुत है। There is sufficient supply. Therefore, there is no reason for panic in the market. I am certain that the Department of Civil Supplies and Consumer Affairs, through which the Government acts in this behalf, will contain the price rise of these commodities.

Thank you, Sir.

श्री नरेश अग्रवाल : सर, माननीय सदन के नेता के जवाब संतोषजनक नहीं हैं सत्य से परे हैं **...(व्यवधान)...** इसलिए हम सदन से वाकट आउट करते हैं। **...(व्यवधान)...** समाजवादी पार्टी सदन से वाक आउट करती है। **...(व्यवधान)...**

(इस समय कुछ माननीय सदस्य सदन से बाहर चले गए)

श्री गुलाम नबी आजाद : माननीय डिप्टी चेयरमैन, हमने माननीय लीडर ऑफ दि हाउस का जवाब सुना और फूड मंत्री का भी इंटरवेंशन सुना। रेल में कैसे दाम बढ़ते हैं, essential commodities में इन महीनों में कैसे दाम बढ़ते हैं, ये भी हम दस साल से बता रहे थे और यही अगर सरकार ने जवाब देना था, तो सरकार बदलने की जरूरत ही क्यों थी, फिर तो सरकार चल रही थी। **...(व्यवधान)...** लेकिन इस देश में इलेक्शन में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, एनडीए की तरफ से हमारे खिलाफ एक मुद्दा 6 महीने छाया कि दस सालों में महंगाई बढ़ी, पेट्रोल के दाम बढ़ गए, डीजल के दाम बढ़ गए, केरोसिन तेल के दाम बढ़ गए और इसलिए आप इस सरकार को हटाओ और हम सरकार चलाएंगे और अच्छे दिन आएंगे। मैं यह मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के लिए अच्छे दिन आ गए, लेकिन इस देश की गरीब जनता के लिए उसी दिन से बुरे दिन आ गए, जिस दिन से भारतीय जनता पार्टी सरकार में आई। इसलिए हम माननीय फाइनेंस मिनिस्टर के जवाब का बड़ा आदर करते हुए, पर्सनली इनके खिलाफ कुछ कहना नहीं चाहते, लेकिन कीमतों में जो वृद्धि हुई है उसे रोकने में बीजेपी की सरकार असफल हो गई है और जनता के साथ जो विश्वासघात है, इस विश्वासघात को हम बर्दाश्त नहीं कर सकते, इसलिए हम **entire opposition** सदन से वॉकआउट करते हैं।

(इस समय कुछ माननीय सदस्य सदन से बाहर चले गए)

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Yes, Mr. Yechury. ..*(Interruptions)*..

SHRI SITARAM YECHURY: Sir, what about forward trading and future trading? ...*(Interruptions)*... What about speculation? ...*(Interruptions)*...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Mr. Sharad Pawar, would you like to say something?

SHRI SITARAM YECHURY: Sir, I have asked a question.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Have you asked a question?

SHRI SITARAM YECHURY: Yes, Sir, I want to know what you are planning to do about speculation in the market. ...*(Interruptions)*...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Okay, okay.

SHRI SITARAM YECHURY: Are you banning forward trading and future trading in essential commodities? ...*(Interruptions)*...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: All right. ...*(Interruptions)*...

SHRI SAT1SH CHANDRA MISRA: Sir, the entire reply. ...*(Interruptions)*...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: I will allow you. ...*(Interruptions)*.. I have called Shri Sharad Pawar. ...*(Interruptions)*..

SHRI SATISH CHANDRA MISRA: ...says that कि उन्होंने जो किया, उसको हम कॉटिन्यू कर रहे हैं और उसी को हम इम्पिलमेंट कर रहे हैं। यह जवाब कोई जस्टिफिकेशन नहीं हुआ कि उसे यूपीए ने और अब पब्लिक के ऊपर हम थोप रहे हैं। उन्होंने जो काम किया था और उसी के लिए वे हटे, तो उसकी बेसिस पर आप यह जस्टिफिकेशन दे रहे हैं कि हम इसको इसलिए कर रहे हैं कि इसका हम लोग एग्री नहीं करते हैं, यह रिप्लाई केवल आँख में धूल झोंकने वाली बात है।

SHRI SITARAM YECHURY: Sir, I just want a clarification on this.

SHRI SATISH CHANDRA MISRA: Sir, we are not satisfied with this; so, we are walking out.

(At this stage, some Hon. Members left the Chamber.)

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Okay. ...*(Interruptions)*...

SHRI SITARAM YECHURY: Are you banning forward and future trading at least for some time in essential commodities?

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Okay. Sharad Pawarji, do you want to say something?

SHRI SITARAM YECHURY: Sir, you please ask the Minister to respond. ...*(Interruptions)*...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: He may respond at the end.

SHRI SITARAM YECHURY: After this only Sharad Pawarji will ask.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: No, no. After him, he may respond but it is up to him.

SHRI SITARAM YECHURY: Sir, an allegation has come that they are working like the UPA-III Government. I don't want to go into that. I am asking only a specific question.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: You just ask. That is enough. ...*(Interruptions)*...

SHRI SITARAM YECHURY: Are you banning forward and future trading at least for some time?

MR. DEPUTY CHAIRMAN: It is up to the Minister to answer or not. Now, Sharad Pawarji.

श्री शरद पवार (महाराष्ट्र) : महोदय, अभी खाद्य मंत्री ने गन्ना किसानों की समस्या के बारे में कुछ विचार सदन के सामने रखे। इससे पहले भी मैंने इनकी प्रेस कान्फ्रेंस देखी थी कि इन्होंने चार डिसिजंस लिए हैं। एक जो इम्पोर्टेड चीनी होती है, उस पर 40 प्रतिश ड्यूटी बढ़ाना, दो इससे पहले सरकार ने जो कदम उठाए थे उसकी समय-सीमा बढ़ाना और उनका तीसरा डिसिज़न एथनॉल के 10 परसेंट blending करने के बारे में था। मेरा सवाल यह है कि क्या यह सच है कि उन्होंने कहा कि जब तक मिल मालिक यह कमिट नहीं करते कि किसानों को वे यह कीमत देंगे, तब तक मैं ऑर्डर नहीं निकालूँगा? आज स्थिति ऐसी है कि इन्होंने इस बारे में अनाउंसमेंट तो कर दी, मगर कोई आर्डर इश्यू नहीं किया। जब तक ऑर्डर इश्यू नहीं होता, तब तक यह कीमत देने की ताकत मिल में नहीं होती है। ये कंडिशनल ऑर्डर इश्यू कर सकते हैं कि हम यह ऑर्डर इश्यू करेंगे, यह आपको करना पड़ेगा, तो ही इस पर अमल करने का आपका अधिकार है, मगर इन्होने केवल अनाउंसमेंट की, आर्डर इश्यू नहीं किया और इसलिए आज गन्ना किसानों को उचित कीमत नहीं मिल रही है।

श्री रामविलास पासवान : सर, अभी आपने सुना कि हमारे साथी चार्ज लगा रहे थे कि हम मिल मालिकों से मिले हुए हैं और इसके कारण ही ऐसा है। हमको यह डर पहले ही था। हमने ऐसा नहीं कहा बल्कि हम सिर्फ इतना ही कहते हैं कि मिल मालिक आकर इस बात का टाइम बाउंड एश्योरेंस दें कि वे गन्ना किसानों के बकाया का पेमेंट कर देंगे। जब वे उसका पेमेंट कर देंगे, उसके बाद सारे निर्णयों को इम्पिलमेंट कर देंगे। इसलिए यह गन्ना मिल मालिकों के ऊपर है कि वे कब आकर यह एश्योरेंस देते हैं, जिससे किसानों का बकाया पेमेंट भी मिल सके और हम लोगों के ऊपर यह चार्ज भी न लगे कि हम किसी एक से मिले हुए हैं।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Hon. Finance Minister, would you like to react to Mr. Yechury?

SHRI SITARAM YECHURY: Since there is no reply to the question of future and forward trading,...

Sir, my hon. friend has raised a valid and very important point. The Government will keep that suggestion in mind.

SHRI SITARAM YECHURY: But, Sir, please announce it today. ...*(Interruptions)*... You take your time. But we think it is valid right now for you to make an announcement. I hope you will make it on Monday. But since you are not making it today, so, in protest, I would like to stage a walk-out'alongwith my Members.

(At this stage, some Hon. Members left the Chamber.)

———